RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ... सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-07, अंक - 46 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 14 अगस्त 2025 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

हमारा सर्व श्रेष्ठ कार्य तभी होगा, हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव तभी पड़ेगा, जब हममें अहंभाव लेश मात्र भी न रहेगा।

स्वामी विवेकानंद

सीहोर हादसाः मौत का जिम्मेदार कौन...?

माही की गूंज। संजय भटेवरा

झाबुआ।

सीहोर जिले में स्थित कुबेश्वर धाम आस्था का नया केंद्र बन चुका है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पहुंचते हैं। हाल ही में श्रावण मास के अवसर पर निकाली गई विशाल कांवड़ यात्रा में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इससे पूर्व भी कई अवसरों पर यहां भगदड़ मच चुकी है, जिसमें लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि, इन हादसों में हुई मौत का जिम्मेदार कौन-प्रशासन या आयोजक...?

निश्चित रूप से किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए पहले प्रशासन को अनुमति के लिए विधिवत लिखित में आवेदन देना होता है, और प्रशासन कुछ शर्तों के अधीन अनुमति जारी करता है। प्रशासन द्वारा लगाई गई शर्तों के तहत मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की जाती है। वहीं कानून के अंतर्गत आमजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है, क्योंकि यह उसकी प्राथमिक भूमिका है। तो क्या यह माना जाए कि, प्रशासन अपनी भूमिका ठीक ढंग से नहीं निभा पाया...?

प्रशासन भीड़ का सही आकलन नहीं कर पाया और उसका ग्राउंड मैनेजमेंट (भीड़ का प्रबंधन) असफल रहा। नतीजन, बेकाबू भीड़ में अफरा-तफरी मच गई और निर्दोषों की जान चली गई।

पूर्व में भी हो चुके हैं हादसे

कुबेश्वर धाम में प्रतिवर्ष रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम भी होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक बार तो सीहोर रोड पर लंबा जाम लग गया था और पंडित प्रदीप मिश्रा को अपनी कथा रद्द करनी पड़ी थी। इसके बाद प्रदेश के तत्कालीन गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी।

उसके बावजूद भी प्रशासन कुबेश्वर धाम में होने वाले आयोजनों के लिए सही व्यवस्था नहीं कर पाया। यह कहीं न कहीं प्रशासन की भी विफलता है। साथ ही, आयोजकों को भी चाहिए कि वे अपनी मूलभूत व्यवस्था में सुधार करें। भीड़ को एक ही जगह एकत्रित न होने दें, आयोजन से जुड़ी प्रशासनिक गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें और भक्तों की आस्था का उचित ध्यान रखें।

भक्त केवल श्रद्धाभाव के कारण ही ऐसे आयोजनों में पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन और आयोजन समिति दोनों की होती है। इसलिए प्रशासन और आयोजन समिति, दोनों मिलकर उचित प्रबंधन करें, ताकि श्रद्धालु जिस श्रद्धाभाव से ऐसे आयोजनों में पहुंचते हैं, वह श्रद्धा बनी रहे और वे सकुशल अपने निवास स्थान पर लौट सकें।

फोर्टिफाइड का मतलब ग्रामीणों को समझाने में नाकाम हो रहा है जिला प्रशासन

फोर्टिफाइड चावल का स्वरूप ही ग्रामीणों को कर रहा विचलित और फैला रहा भ्रम

माही की गूंज, झाबुआ।

पिछले लंबे समय से सरकारी खाद्य वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किए जा रहे चावलों को लेकर कई शंका और कुशंकाएँ ग्रामीणों में फैली हुई है। सरकार और उसका प्रशासन ठेठ ग्रामीण अंचल में बसे ग्रामीणों को यह समझाने में अब तक नाकाम ही साबित हुआ है कि, आखिर फोर्टिफाइड चावल होता क्या है? यही सबसे बड़ा कारण है कि, इसको लेकर ग्रामीण और अशिक्षित लोग तो ठीक पढ़े-लिखे युवा भी समझ नहीं पा रहे है। जब भी वे सामान्य चावलों के बीच फोर्टिफाइड चावल के दाने देखते है तो वे इसे प्लास्टिक के चावल ही करार देते दिखाई देते है। क्योंकि यह प्राकृतिक चावल से दिखने में थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। ग्रामीणों में यह अफवाह भी है कि, इसके खाने से शरीर में नुकसान भी होता है। इसमें गलती जिले के उन ग्रामीणों की भी नहीं है क्योंकि वे बैचारे या तो अशिक्षित है या उनमें इतनी समझ ही नहीं है कि, फोर्टिफाइड का मतलब समझ सके।

इसको लेकर प्रशासन ने कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया है। इसके विपरीत प्रशासन या खाद्य विभाग सिर्फ प्रेसनोट जारी कर यह तर्क दे रहा है कि, ''फोर्टिफाईड चावल जनवरी 2023 से मध्यप्रदेश के सभी जिलों में वितरित किया जा रहा है। चावल को फोर्टिफाईड करने के लिए सामान्य चावल में आयरन, विटामिन बी-12, और फोल्लिक एसिड से युक्त फोर्टिफाईड चावल के दाने 1 प्रतिशत की मात्रा मे, मतलब 100 कि.ग्रा सामान्य चावल में 1 कि.ग्रा. फोर्टिफाईड चावल के दाने मिलाए जाते है। फोर्टिफाईड चावल के दाने सामान्य चावल की तरह दिखते है। फोर्टिफाईड चावल के दाने पकाते या धोते समय अलग से दिखे तो इन चावलों को अलग न करे और इनका सामान्य चावल की तरह सेवन करे। ध्यान रखे, यह प्लास्टिक चावल नहीं है, बल्कि पोषण युक्त फोर्टिफाईड चावल है। अतः भ्रामक जानकारियों एवं अफवाहों से सावधान रहें।

इसी प्रकार आयोडीन एवं आयरन युक्त डबलफोर्टिफाईड नमक ''वन्या प्लस÷ नाम से म.प्र. के 33 जिलों (आदिवासी बाहुल्य जिले, उच्च प्राथमिकता वाले जिले एवं आंकाक्षी जिले) की शासकीय उचित मूल्य दुकान से 1 रुपया प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जा है। आमजन मे यह भ्रम है कि उक्त डबलफोर्टिफाईड नमक में काले बारिक कण पाये गये है जोकि वास्ताविकता में आयरन (लौह तत्व) के कण है, इसके सेवन से खून की कमी (एनीमिया) दूर होती है।

ग्रामीणों को प्रोसेसिंग समझाना जरूरी

सामान्य तौर पर यह जानकारी आम और साधारण व्यक्ति की समझ से परे दिखाई पड़ती है। इसमें कहीं भी यह नहीं बताया गया कि, फोर्टिफाइड चावल किस तरह से तैयार किया जाता है। चावल में आयरन, विटामिन बी-12, और फोल्लिक एसिड से युक्त फोर्टिफाईड चावल के दाने 1 प्रतिशत की मात्रा मे, मतलब 100 कि.ग्रा सामान्या चावल में 1 कि.ग्रा. फोर्टिफाईड चावल के दाने मिलाए जाते है, सिर्फ यही बताया गया है। चावल में किस तरह के विटामिन कैसे मिलाए जाते है यह नहीं बताया गया! जबकि फोर्टिफाइड चावल की पूरी प्रोसेसिंग कम से कम झाबुआ-आलीराजपुर जैसे जिलों में तो ग्रामीणों को समझाना ही चाहिए ताकि वे इसे समझ सके कि यह कोई प्लास्टिक का चावल नहीं है, और ना ही यह प्राकृतिक चावल है।

प्रशासन चौपाल के जरिए करे ग्रामीणों से खुलकर बातचीत

हालांकि पढ़े लिखे और समझदार तबके के लोगों में इसको लेकर कोई अफवाह या विवाद नहीं है, लेकिन शंका जरूर है, वह शंका हम आगे बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां ठीक नहीं है वहां लोग यही समझ रहे है कि सरकार जो चावल वितरण कर रही है वह मिलावटी है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार व उसके तंत्र को खुलकर मैदान में आना चाहिए। ग्रामीणों से इस विषय पर चौपाल लगाकर खुलकर बातचीत होनी चाहिए। मगर अब तक कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। जो जतन प्रशासनिक तंत्र प्रेसनोट जारी करके कर रहा है वह इस अशिक्षित जिले में ना काफी है। क्योंकि अखबरों का हर ग्राम या ग्रामीण तक पहुंचना संभव नहीं है, अखबार या सूचना पहुंच भी जाए तो जिले की एक बड़ी आबादी अब भी अशिक्षित या अल्पशिक्षित ही है। इसलिए तंत्र के प्रेसनोट जारी करने का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन ने खाद्य वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों के सेल्समेनों की ऐसी कोई सार्वजनिक ट्रेनिंग या प्रशिक्षण नहीं दिया है कि, वे ग्रामीणों को समझा सके कि आखिर यह फोर्टिफाइड चावल क्या है और कैसे बनता है।

इस तरह बनता है फोर्टिफाइड चावल।

चावलों को फोर्टिफिकेशन करने का तरीका यह है कि इन्हें तैयार करने के लिए चावल को पीसकर इसका पाउडर तैयार किया जाता है। इसके बाद इस पाउडर में पोषक तत्वों वाला पाउडर मिलाकर गूंथ लिया जाता है। अब इस गुंथे हुए आटे को मशीनों द्वारा चावल का आकार देकर सुखा लिया जाता है, ताकि ये सामान्य चावल जैसा ही दिखे। जैसा कि प्रशासन व खाद्य विभाग द्वारा जारी प्रेसनोट में बताया गया कि, फोर्टिफाईड चावल के दाने 1 प्रतिशत की मात्रा में, मतलब 100 किलो ग्राम सामन्य चावल में 1 किलो ग्राम फोर्टिफाईड चावल के दाने मिलाए जाते है। फिर इसके बाद यह खाद्य वितरण प्रणाली द्वारा प्रदेश की तमाम सरकारी राशन दुकानों पर पहुंचता है और यहां से आम नागरिक को वितरण किया जाता है। कुल मिलाकर फोर्टिफाइड चावल एक कृतिम चावल है जिसे मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है।

यह भी एक यक्ष प्रश्न ?

यह तो हो गई उन लोगों के लिए बात जो फोर्टिफाइड चावल का मतलब नहीं समझ पा रहे है। लेकिन जो लोग फोर्टिफाइड चावल का मतलब समझते है, उनके मन में भी कई तरह की शंकाएं इस बात को लेकर है कि, अगर जिस तरह से चावल को पीसकर इसमें विटामिन, आयरन और फोलिक एसिड मिलाया जा रहा है और फोर्टिफाइड चावल तैयार किया जा रहा है। उसी तरह चावल को पीस कर उसमें कुछ और भी तो मिलाया जा सकता है? यह और बात है कि, अभी यह काम सिर्फ सरकार कर रही है। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि चावल, व्यापारी और मिलाटव खोर यही फार्मुला अपना कर मार्केट में कोई मिलावटी या नकली चावल नही बैच पाएंगे! जबकि सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियों वायरल हो रहे कि, जिसमें चीन या किसी अन्य देश की कम्पनियां नकली चावल बनाकर बैच रही है। अगर इनको सच मान लिया जाए तो यह तय है कि, भले ही सरकार इस फार्मुले को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर रही है, मगर मिलावटी और कालाबाजारी करने वाले लोग इसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे? सरकारी राशन दुकानों को छोड़ भी दे तो क्या बाजार में प्राकृतिक चावल ही आ रहा है या फिर सरकार जिस तरह फोर्टिफाइड चावल बनाकर वितरण कर रही है उसी तरह कालाबाजारी करने वाले चावलों में मिलाटव नही कर सकेंगे... यह यक्ष प्रश्न है।

एक जगह शिकायत पर कार्यवाही बाकी, कई जगह धड़ल्ले से काम जारी

माही की गूंज, खवासा।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के नजदीक नेशनल हाईवे पर अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे में स्मार्ट डिजिटल इंडिया' के तहत केबल बिछाने का कार्य पीपीटी मॉडल पर डी. आर. अग्रवाल कंपनी द्वारा किया जा रहा है। जिसमें भामल-बाजना मार्ग, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आता है, पर विभाग के बिना अनुमति के ठेकेदार द्वारा शोल्डर खोद दिए गए। इस पर ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों को सूचना दी, जिसके पश्चात लोक निर्माण विभाग की निद्रा भंग हुई और पेटलावद के सब इंजीनियर भारती बघेल, खवासा पुलिस चौकी के बल के साथ मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। वहां बिना अनुमति मुख्य मार्ग के नीचे खुदाई की जानकारी सही पाई गई। कई विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस तरह बिना परमिशन मुख्य मार्ग की खुदाई नहीं की जा सकती है।

केबल बिछाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। मौके पर पहुंचकर विभागीय अधिकारियों ने पंचनामा बनाया और इस्टीमेट बनाकर 3 लाख 70 हजार का जुर्माना वसूलने के लिए लोक निर्माण विभाग झाबुआ को पत्र भेजा।

अब सवाल यह उठता है कि, शिकायत होने पर कार्यवाही की गई, लेकिन अगर यहां शिकायत नहीं की जाती तो यह कार्य बिना रोक-टोक पूरा हो जाता। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई जगह केबल बिछाने वाले ठेकेदारों ने मध्यप्रदेश शासन की सड़कों को इस तरह क्षतिग्रस्त किया होगा उनका क्या...? यही नहीं, इस एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान भी कई जगह बिना रॉयल्टी के खनन किया गया और मध्यप्रदेश शासन को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया।

आम जनता के बीच चर्चा है कि, शासन के कार्यों में बड़ा गोलमाल है। कई जगह ऐसे कार्य हो रहे हैं, लेकिन कार्यवाही केवल आम जनता की शिकायत पर हो रही है। तो विभागीय अधिकारियों का क्या काम है...? विभाग कब स्वविवेक से निर्णय लेना प्रारंभ करेगा...?

तिरंगा यात्रा और पर्यावरण रैली में उमड़ा जन-जन का उत्साह

माही की गूंज, बामनिया।

मध्यप्रदेश शासन के आदेश, जिला कलेक्टर झाबुआ के निर्देशन एवं सहायक आयुक्त आदिवासी जनजाति विकास विभाग झाबुआ के मार्गदर्शन में, विकासखंड शिक्षा अधिकारी पेटलावद की गरिमामयी उपस्थिति में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बामनिया में तिरंगा यात्रा एवं पर्यावरण रैली का आयोजन हुआ।

इस अवसर पर भारत स्काउट एवं गाइड प्रभारी मंगलेश राठौर, सुभाष स्काउट ग्रुप के साथ जिला प्रशिक्षण आयुक्त (लीडर ट्रेनर) ओमप्रकाश त्रिपाठी, विद्यालय प्राचार्य सुखराम गरवाल, रैली प्रभारी राकेश मैड़ा, द्वारका लाल मेघवाल, उप प्राचार्य निजामुद्दीन कुरैशी, पर्यावरण रैली प्रभारी प्रशांत पाटीदार एवं वरसिंह सिंगाड़ की विशेष उपस्थिति रही।

विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा और प्रेरणादायक स्लोगन लेकर मामा बालेश्वर दयाल आश्रम मोहल्ला, मस्जिद गली और बामनिया के प्रमुख चौराहों से होते हुए जैन मंदिर, पंचायत मार्ग से विद्यालय खेल प्रांगण तक रैली निकाली।

देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण के जोशीले नारों से गलियाँ गूंज उठीं

कार्यक्रम का समापन विद्यालय खेल परिसर में राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ हुआ। प्राचार्य सुखराम गरवाल ने विद्यार्थियों को राष्ट्रप्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, जबकि जिला प्रशिक्षण आयुक्त ओमप्रकाश त्रिपाठी ने सभी सहयोगियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

अधूरे छात्रावास निर्माण कार्य और भ्रष्टाचार की मुंह जुबानी

निर्माणाधीन भवन, जिसे जनजाति विभाग को सुपुर्द भी नहीं किया गया है, उसके पूर्व ही छात्रावास का निर्माण भ्रष्टाचार की मुँहजुबानी बयाँ कर रहा है

माही की गूंज, खवासा।

हमारे सिस्टम ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है, यह कहा जाता है। लेकिन कहते हैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं कही जा सकती है। क्योंकि वाकई में हमारे मध्यप्रदेश में ऐसे नए-नित भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार हो रहे हैं यह कहने की आवश्यकता नहीं, बल्कि निर्माण कार्य में तो भ्रष्टाचार सहज ही स्पष्ट रूप से उसकी मुंह जुबानी ही बयां कर रही है।

भ्रष्टाचार के इस शिष्टाचार रूपी सिस्टम का एक छोटा सा उदाहरण थांदला जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत नारेला में हो रहे छात्रावास निर्माण में भी आकर देखा जा सकता है कि, किस तरह से भवन सुपुर्दगी के पूर्व ही यह नवनिर्माणधीन छात्रावास भवन अपनी भ्रष्टाचार की मुंह जुबानी बयां कर रहा है। बताया जाता है कि ग्राम पंचायत नारेला में लागत करीब 3 करोड़ 33 लाख से 50 सिटर कन्या छात्रावास भवन का नवनिर्माण हो रहा है।

उक्त निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन बीआईयू विभाग है तथा विभाग से टेंडर किसी अग्रवाल एंड कंपनी धार ने लिया है। खैर, उक्त छात्रावास के निर्माण कार्य की अवधि पूर्ण हो चुकी है और अब भी निर्माण कार्य अधूरा है, कहा जा रहा है। यानि कि निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा लेट-लतीफी तो की ही जा रही है, लेकिन पीआईयू विभाग के इंजीनियर व बड़े अधिकारियों की मिलीभगत कहें या अनदेखी पर, जो करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए में बनने वाला यह नवनिर्माण भवन अभी जनजाति विभाग को सुपुर्दगी में नहीं किया है। उसके पूर्व ही अब तक जो निर्माण हुआ है, उक्त छात्रावास निर्माण में ही बनी दीवारें एवं भवन

अपनी भ्रष्टाचार की मुंह जुबानी बयां कर रहा है, जिसमें भवन निर्माण को देखते ही पता चलता है कि, भवन में कितनी जगह अभी से दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में ठेकेदार कार्य पूर्ण कर जब जनजाति विभाग को सुपुर्द करेगा, उसके बाद यह भवन डिस्मेंटल कार्य क्षमता कितने वर्ष की रहेगी, नहीं कहा जा सकता है।

उक्त अनियमितता पूर्ण व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा इस निर्माण को लेकर नारेला पंचायत के सरपंच बालु वसुनिया ने भी आरोप लगाया कि, ठेकेदार व अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ही शासन की योजना को धूमिल करते हुए नारेला में बन रहे कन्या छात्रावास भवन के नवनिर्माण में जमकर अनियमितता व भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिसे हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त छात्रावास के निर्माण में अब तक बनी दीवारें व निमार्ण स्वतः ही बोल रही हैं कि यहां दीवारों में दरारें व छत में भ्रष्टाचार रूपी कार्य किस निचले स्तर का किया गया है। वहीं, ग्रामीणों का भी कहना है कि, हमारे सिस्टम ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। इसीलिए यह छात्रावास भवन अपना पूर्ण मूर्त रूप लेने के पहले ही अपने भ्रष्टाचार की कहानी लिख चुका है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। फिर भी ग्रामीणों ने सरकार से मांग की कि, सरकार की महत्वपूर्ण योजना शिक्षा को बढ़ावा देना इसी के तहत नारेला में बनाए जा रहे उक्त कन्या छात्रावास निर्माण की जांच करें और संबंधित ठेकेदार व अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें तथा उक्त निर्माण में गुणवत्ता का स्वरूप दें। अब देखना है कि, शासन व प्रशासन के नुमाइंदे उक्त भ्रष्टाचार की ओर अपनी निगाहें डाल उक्त भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे...? या भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया गया है, यह संदेश मूर्त रूप से देगे...?

सोसायटी से वितरित चावल में प्लास्टिक चावल जैसा दाना होने की शंका पर भड़के ग्रामीण

मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने बताया फोर्टिफाइड चावल, प्रचार -प्रसार के अभाव के कारण हो रही परेशानी

माही की गूंज, पेटलावद।

शासन की योजना के तहत सोसाइटीयों के माध्यम से एक रुपए किलो अनाज, गेहूं, चावल आदि वितरित किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में सोसाइटी से मिले अनाज को ही खाया जाता है। वर्षों से वितरित चावल के खराब होने और खराब चावल वितरित होने की खबरें आती रही हैं, लेकिन ग्राम पंचायत बामनिया के चित्तौड़ी रुंडी फलिए में कुछ ग्रामीणों को सोसाइटी से मिले चावल के दानों में अलग से दिखने वाले चावल के दाने दिखाई दिए।

सोसाइटी से वितरित किए जाने वाला चावल।

इस प्रकार का अलग सा चावल जैसा दिखने वाला दाना जो सोसाइटी के चावल में मिला हुआ है।

शंका होने पर अलग से दिखने वाले चावल के दानों को अलग कर खाने-चबाने की कोशिश करने पर चावल प्लास्टिक के दाने होने की शंका हुई। ग्रामीणों के द्वारा इसकी जानकारी स्थानीय मीडिया तक पहुंचाई, जिसके बाद मामला सामने आया। चावल में मिले दानों की जानकारी के लिए स्थानीय सोसाइटी के मैनेजर भेरूलाल पाटीदार से जानकारी ली गई तो उन्होंने भी इस प्रकार के चावल की कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। जिसके बाद चावल को अलग-अलग तरीके से परखने के बाद यह तो तय हो गया कि सोसाइटी से मिले चावल में अलग से दिख रहे ये दाने चावल नहीं हैं।

मीडिया और सोशल मीडिया में खबर आने के बाद हरकत में आया प्रशासन

इस प्रकार का चावल क्यों और किस लिए वितरित किया जा रहा है, सोसाइटी के सेल्समैन से लेकर मैनेजर तक को इसकी जानकारी नहीं है। खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्लास्टिक के चावल जैसे लग रहे इन दानों पर अपनी सफाई पेश करते हुए प्रेस नोट जारी कर चावल को फोर्टीफाइड चावल बताया।

प्रेस नोट में जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि, फोर्टीफाइड चावल जनवरी 2023 से मध्यप्रदेश के सभी जिलों में वितरित किया जा रहा है। चावल को फोर्टीफाइड करने के लिए सामान्य चावल में आयरन, विटामिन बी-12, और फॉलिक एसिड से युक्त फोर्टीफाइड चावल के दाने 1 प्रतिशत की मात्रा में, मतलब 100 किलोग्राम सामान्य चावल में 1 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल के दाने मिलाए जाते हैं। फोर्टीफाइड चावल के दाने सामान्य चावल की तरह दिखते हैं।

प्रचार-प्रसार की कमी के चलते ग्रामीणों में शंका

इस प्रकार का मामला पहली बार सामने आया जब चावल खाने वाले ग्रामीणों ने ही चावल में प्लास्टिक के चावल होने की आशंका व्यक्त की, जिसका मुख्य कारण भारी प्रशासनिक लापरवाही को माना जा सकता है। चावल में शरीर के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाली चीजें मिलाई जा रही हैं, इसका कोई प्रचार-प्रसार सोसाइटी स्तर तक नहीं किया गया, न ही इसको लेकर प्रशासन का कोई जागरूकता अभियान या कोई बैनर-पोस्टर सोसाइटीयों पर देखे गए।

ज्यादातर सेल्समैन से लेकर सोसाइटी मैनेजर तक इस बात से अनभिज्ञ हैं। देखा जाए तो पूरा मामला प्रशासनिक लापरवाही का है, जिसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही होना थी, लेकिन मीडिया में आई खबरों को प्लास्टिक के चावल को अफवाह मात्र बताकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली।

छात्र-छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा

माही की गूंज, खवासा।

भामल संकुल के अंतर्गत हाई स्कूल एवं मिडिल स्कूल के छात्र-छात्राओं ने सोमवार को तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी हाथों में तिरंगा लिए हुए देशभक्ति के नारे लगाते हुए पूरे गांव में रैली के रूप में निकले।

हर घर तिरंगा अभियान को सार्थक बनाने के उद्देश्य से निकाली गई इस यात्रा में छात्र-छात्राएं तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के जयकारे लगा रहे थे। तिरंगा यात्रा भामल हाई स्कूल से प्रारंभ होकर पूरे गांव में घूमी और पुनः हाई स्कूल परिसर में पहुंची।

वापसी के बाद राष्ट्रगान का आयोजन किया गया और इसके साथ ही यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को तिरंगे के केसरिया, सफेद और हरे रंग के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर घर तिरंगा का संदेश पूरे गांव में पहुंचाया गया।

हर घर तिरंगा को लेकर ग्राम पंचायत ने निकाली यात्रा

माही की गूंज, खवासा।

ग्राम खवासा में बुधवार को सुबह 11 बजे ग्राम पंचायत खवासा से लेकर पूरे नगर में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीत गाते हुए पूरे नगर में रैली निकाली। यात्रा में बच्चों के साथ शिक्षक, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः ग्राम पंचायत खवासा पहुंची, जहां देशभक्ति के गीतों के साथ राष्ट्रगान हुआ और इसके बाद यात्रा का समापन किया गया।

इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष मायादेवी प्रेमसिंह चौधरी, खवासा चौकी प्रभारी एडमिरल तोमर सहित प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षक उपस्थित थे।

किसान यूनियन का ज्ञापन लेने नहीं पहुंची एसडीएम, धरने पर बैठे किसान

किसान फसल बीमा के मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ धोखे का आरोप

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में एक बार फिर स्थिति बिगड़ी देखी गई, जब शांति पूर्ण ढंग से प्रधानमंत्री के नाम अपना ज्ञापन लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान पहुंचे थे। किसान यूनियन के महेंद्र हामड़ ने बताया कि, ज्ञापन देने से पूर्व एसडीएम द्वारा समय दिया गया था, उसी समय पर पहुंचे लेकिन एसडीएम ज्ञापन लेने और किसानों की बात सुनने के लिए नहीं पहुंची। एसडीएम के नहीं आने से किसानों में नाराजगी देखी गई और एसडीएम के व्यवहार से नाराज किसान कार्यालय के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लग गए।

ट्रैक्टर रैली निरस्त

यूनियन के जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि, किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाना था। हमारे द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन होना था, लेकिन एसडीएम के कहने पर ट्रैक्टर रैली निरस्त कर दी। इसके बाद भी किसानों को अपमानित कर उनका ज्ञापन लेने एसडीएम नहीं पहुंची। किसानों की मांगों को लेकर प्रेम भूरिया और बलराम पाटीदार ने बताया कि, हमारी मुख्य मांगों में किसानों की सोयाबीन की फसल के लिए 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल का भाव, किसानों को फसल बीमा योजना का सही लाभ सहित कई मांगें प्रधानमंत्री के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से रखी गई हैं। नाराज किसान काफी देर तक नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद मौके पर थाना प्रभारी निर्भय सिंह भूरिया एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश देकर किसानों का धरना खत्म करवाया, ज्ञापन लिया और सोमवार को किसानों की मांगों को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक निर्धारित करने के आश्वासन के साथ धरना समाप्त करवाया गया।

किसानों के साथ मुआवजे के नाम पर धोखा

किसानों के धरने में ऐसे भी किसान पहुंचे थे, जिनके साथ फसल बीमा राशि के नाम पर धोखा किया गया। रत्न लूना गामड़ निवासी बरडिया ने बताया कि, मेरे खाते में फसल बीमा राशि के नाम पर शासन द्वारा 20 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि बीमे की प्रीमियम 432 रुपए वसूले गए थे। कचरीबाई सोलंकी, बरडिया के पुत्र ने बताया कि, उनको मुआवजा राशि के 19 रुपए क्लेम मिला और 378 रुपए की प्रीमियम जमा की गई। किसान संघ के अध्यक्ष ने बताया कि, सरकार किसानों को मुआवजा राशि के नाम पर धोखा दे रही है। किसानों के खातों से बिना बताए फसल बीमा की राशि काटी जाती है, कोई रसीद या पॉलिसी तक नहीं दी जाती और फसल खराब होने पर सारे सर्वे करने के बाद भी क्लेम राशि दो अंकों में देकर किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है।

गायत्री परिवार का पंचकुंडी यज्ञ संपन्न

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद तहसील, जिला झाबुआ द्वारा पंचकुंडी यज्ञ का आयोजन दीप, यज्ञ कलश, यात्रा एवं यज्ञ के साथ स्थानीय आंजना धर्मशाला में संपन्न हुआ।

रतलाम गायत्री परिवार के नरेंद्र पाठक, सुरेंद्र जोशी, गोपाल चौहान, चित्रा जोशी, वीणा पाठक, थांदला के राजाराम पाटीदार, करवड के मोतीलाल गामड़ व निलेश राठौड़ ने सुमधुर गीतों की प्रस्तुति दी। यज्ञशाला को सुंदर ढंग से सजाया गया था। एक दिन पूर्व दीपयज्ञ का आयोजन हुआ तथा प्रातःकाल कलश यात्रा के माध्यम से संदेश दिया गया। इस दौरान जीवन जीने की कला का मर्म बताया गया। साथ ही वृक्षारोपण, युवा जोड़ों का मार्गदर्शन, व्यसन मुक्ति, महिला व युवा मंडल गठन की प्रेरणा दी गई।

ज्योति कलश यात्रा का पूजन एवं स्वागत करने का आह्वान किया गया। उपस्थित परिजनों ने यज्ञ, दीपयज्ञ व साधना के माध्यम से जागृति बढ़ाने का संकल्प लिया। उपस्थित परिजनों को मंत्रलेखन का महत्व बताते हुए निशुल्क पुस्तिकाएं ललिता भट्ट, रवि बाला एवं इशिका भट्ट द्वारा वितरित की गईं।

कार्यक्रम में राधेश्याम जवा (अंजना), दशरथ लाल अंजना, वीरेंद्र अंजना, नारायण अंजना, योगेश्वर अंजना, मोहनलाल अंजना, हरिओम अंजना, गोपाल अंजना, पुष्कर अंजना एवं महिला मंडल का भरपूर सहयोग रहा। करडावद के वीकेंद्र सिंह अंजना ने पंचकुंडी यज्ञ कराने का संकल्प लिया। पेटलावद के मोहन भाई गहलोत, राजेश पालीवाल, राजेंद्र मौर्य, भैरू भाई पाटीदार, रजनीकांत शुक्ला, गंगाराम, अशोक भट्ट ने यज्ञ का लाभ लिया। राधेश्याम अंजना ने आभार व्यक्त किया तथा संचालन जीवन भट्ट ने किया।

गूंज खबर का असर

कार्रवाई करने पहुंची बीएमओ की टीम बिना कार्रवाई के बैरंग लौटी

कार्रवाई से पहले झोलाछाप डॉक्टर को किसी ने विभीषण की भूमिका अदा कर दी, जिसकी वजह से सब बंद करके चले गए

माही की गूंज, खवासा।

ग्रामीण अंचलों में अवैध चिकित्सक बिना किसी डर व कार्रवाई के जमकर एलोपैथिक पद्धति से इलाज कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का अमला कार्रवाई करने के लिए पहुंचता है, उससे पहले ही इनको सूचना मिल जाती है। जिसके बाद तत्काल यह अपने क्लीनिक बंद करके मरीजों को बाहर निकाल देते हैं। बताते हैं, झाबुआ जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहां कई अवैध चिकित्सक जो आठवीं-दसवीं तक पढ़े हुए हैं और जो चिकित्सक पढ़े हुए हैं, उन्होंने जिस पद्धति से डिग्री प्राप्त की है, उसी पद्धति से इनको इलाज करना है।

लेकिन खवासा सहित आसपास क्षेत्र में कई जगह बिना पंजीयन के अवैध चिकित्सक कुकुरमुत्तों की तरह जमे हुए हैं। इनके पास न तो एमबीबीएस की डिग्री है, न ही एलोपैथिक पद्धति से इलाज करने का अधिकार है। जिससे कई बार ग्रामीणों को इन अवैध चिकित्सकों से इलाज कराने पर अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इनसे महीनाबंदी लेकर मामले को सेटअप कर लेते हैं और कार्रवाई के नाम पर ढकोसला पीटते हुए नजर आते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है।

पिछले दिनों टीएल बैठक में कलेक्टर नेहा मीणा ने इन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। झाबुआ जिले सहित मेघनगर व पेटलावद में कार्रवाई हो रही है, लेकिन थांदला तहसील के अंतर्गत आसपास क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करने के बजाय इनका संरक्षण देता हुआ नजर आ रहा है। यह ग्रामीणों का इलाज करते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं।

माही की गूंज ने पूर्व में भी तीन समाचार प्रकाशित किए थे, लेकिन अधिकारी समाचार प्रकाशित होने के बाद इन अवैध चिकित्सकों पर कार्रवाई करने के बजाय नोटिस-नोटिस का खेल खेलकर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिससे ग्रामीण अंचलों में यह लोग बिना किसी रोक-टोक के इलाज कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, शनिवार व रविवार को बीएमओ थांदला भुवन सिंह डावर ने अपनी गाड़ी से खवासा सहित भामल में अवैध चिकित्सकों के यहां भ्रमण किया था, लेकिन बीएमओ साहब को सभी दुकानें बंद मिलीं। अब यहां सवाल यह उठता है कि, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है, तो इन अवैध चिकित्सकों को ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति प्राप्त है, जो कार्रवाई होने से पहले इनको सूचना देकर क्लीनिक बंद करवाती है।

यहां सबसे बड़ा प्रश्न है इससे तो यही जिक्र होता है कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत व महीनाबंदी के चलते इन पर कार्रवाई करने के बजाय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संरक्षण देते हुए नजर आते हैं। तभी तो यह कार्रवाई से पहले भूमिगत हो जाते हैं। खवासा सहित आसपास क्षेत्र में अवैध चिकित्सकों की काफी भरमार है। इनके पास किसी तरह का एलोपैथिक पद्धति से इलाज करने का अधिकार प्राप्त नहीं है और यह धड़ल्ले से एलोपैथिक पद्धति से इलाज करते हैं, जबकि यह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग है कि कार्रवाई नहीं कर रहा है।

मामले में खवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ डॉक्टर राकेश निनामा ने बताया कि, खवासा में किसी के पास एलोपैथिक पद्धति से इलाज करने का अधिकार नहीं है। यह आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक होते हैं, इनको एलोपैथिक पद्धति से इलाज करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह शासन के स्पष्ट निर्देश हैं। अभी इनको झाबुआ व थांदला में तलब किया गया था, यह कितने लोग वहां जाकर अपनी डिग्री आदि दिखा पाए हैं, यह तो बीएमओ सर बता पाएंगे, लेकिन इनको इस तरह से एलोपैथिक पद्धति से इलाज करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इनके ऊपर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

मामले को लेकर थांदला बीएमओ भुवन सिंह डावर से चर्चा की तो माही की गूंज को बताया कि, हम कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हमारे आने से पहले ही इनको किसी ने सूचना दे दी, जिसकी वजह से सब बंद करके चले गए हैं। लेकिन बहुत जल्द हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि, इनके पास किसी तरह का एलोपैथिक पद्धति से इलाज करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह काफी समय से लोगों का इलाज कर रहे हैं। बहुत ही जल्द इनके ऊपर गोपनीय तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय

संतुलित व दीर्घकालिक दृष्टिकोण की जरूरत

देश में आवारा कुत्तों के संकट को लेकर गाहे-बगाहे सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली के आवारा कुत्तों को लेकर आए सख्त निर्देश ने इस बहस को नया मोड़ दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार व स्थानीय निकायों से कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह के भीतर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया जाए। हालांकि, समस्या की व्यावहारिक दिक्कतों को लेकर कई यक्ष प्रश्न हैं क्योंकि फिलहाल कुत्तों के लिये ऐसे आश्रय स्थल उपलब्ध नहीं हैं। निस्संदेह, जन सुरक्षा की चिताएं अपनी जगह जायज हैं। बताते हैं कि दिल्ली में रोजाना 2000 तक कुत्ते के काटने की घटनाएं होती हैं। साथ ही रेबीज़ के मामले भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बड़ी समस्या का समाधान सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नहीं होना चाहिए। यहां उल्लेखनीय है कि बीते साल देशभर में कुत्तों के द्वारा काटने के बाइस लाख मामले सामने आए हैं। निस्संदेह, यह एक जटिल चुनौती है और इसके समाधान के लिये एक दीर्घकालिक, तार्किक व परामर्शी रणनीति की आवश्यकता है। इस अभियान में नगर निकाय, पशु चिकित्सक, पशु कल्याण से जुड़े संगठनों और स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी है। निर्विवाद रूप से इस संकट के मूल में असली समस्या खराब शहरी नियोजन,पशु जन्म नियंत्रण यानी एबीसी तथा टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से जुड़ी खामियों की है। देश के शहरों, कस्बों और गांवों के कूड़े के ढेर खुले बूचड़खानों के कचरे से भरे रहते हैं। जहां आवारा कुत्तों की आबादी फल-फूल रही है। नगर निकायों द्वारा वर्षो से चलाए जा रहे नसबंदी अभियान और रेबीज़-रोधी टीकाकरण अभियान इन आवारा कुत्तों की संख्या को कम करने में विफल रहे हैं। निर्विवाद रूप से इस मद के लिये पर्याप्त बजट न होना और कर्मचारियों की कमी इन प्रयासों में बाधा डालती रही है। इस बीच सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर आए दिन टकराव देखा जाता रहा है।

दरअसल, देश में पशु प्रेमियों की भी एक बड़ी आबादी है। भारत में पशु-पक्षियों के कल्याण व संरक्षण की समृद्ध परंपरा रही है। गाय व श्वान का ग्रास देना संस्कृति का हिस्सा रहा है। सोमवार को दिल्ली में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में भेजने के खिलाफ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया तो कुछ लोग हाथ में कई तख्तियां लिए हुए थे, जिसमें लिखा था कि काल भैरव सब देख रहे हैं। दरअसल, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जीव संरक्षण के लिये हर देवी-देवता के साथ वन्य जीव, पशु-पक्षियों को दर्शाया गया है। यहां तक कि श्राद्ध के अवसर पर गाय, कौवे व कुत्ते के लिये अन्न ग्रास निकाला जाता है। सदियों से मनुष्य के अंग-संग कुत्ता रहा है। कहा जाता है कि पांडवों के स्वर्गारोहण के वक्त उनके साथ एक श्वान चला था। लेकिन आज शहरों में फ्लैट संस्कृति में पालतू जानवरों की भूमिका खत्म होने से वे सड़कों पर आ गए। यहां सवाल उनके आक्रामक होने पर भी हैं। दरअसल, आम लोग मांसाहारी भोजन के अवशेष कचरे में फेंक देते हैं, जिससे उनमें आक्रामकता आती है। वहीं जानवरों में असुरक्षाबोध भी उन्हें आक्रामक बना देता है। दुनिया के तमाम छोटे-बड़े देशों ने इस समस्या के निवारण हेतु समाधान निकाले हैं। भारत जैसे विशाल देश में संसाधनों के अभाव में पशु कल्याण की प्राथमिकता व्यावहारिक नहीं है। विदेशों में पालतू कुत्तों को पालना भी बहुत महंगा है और सख्त कानूनों से संख्या का नियमन भी किया गया। वहां कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण के लिये पुलिस बल तैनात किए गए हैं। साथ ही कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और लोगों को इन्हें गोद लेने के लिये प्रेरित करके समस्या का समाधान तलाशा गया। भूटान का उदाहरण सामने है जिसने व्यापक वित्त पोषित राष्ट्रीय अभियान के जरिये कुत्तों की पूर्ण नसबंदी का लक्ष्य हासिल किया। दरअसल, हमारे शहरों में एक एकीकृत मॉडल अपनाना चाहिए। जिसमें बड़े पैमाने पर नसबंदी व टीकाकरण का विस्तार शामिल हो। वहीं केवल निर्दिष्ट समय और आरडब्ल्यूए द्वारा प्रबंधित स्थानों पर कुत्तों का भोजन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन में भी सुधार करने की जरूरत है। साथ ही विभिन्न समुदायों को विरोधियों के रूप में नहीं, बल्कि भागीदारों के रूप में संगठित किया जाना चाहिए।

विषमता की खाइयां पाटना वक्त की जरूरत

विश्वनाथ सचदेव

स्वराज में राहत तो होगी/ मज़दूर मगर भूखा होगा/ उसके बदले की रोटी/ दौलत वाला खाता होगा... आज़ादी चीज तो अच्छी है/ लेकिन है पैसे वालों की/ मजदूर को मजदूरी करनी/ गोरों के बजाय कालों की...।' यह पंक्तियां किसने लिखी हैं, यह तो नहीं पता, पर इतना अवश्य पता है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान कुछ लोग इस तरह के गीत भी गाया करते थे। मैंने अपने पिताजी से बचपन में ये पंक्तियां सुनी थीं और यह बात वे तब कहते थे जब देश में आर्थिक या सामाजिक विषमता का कोई मुद्दा उठता था। समानता और बंधुता के सारे दावों के बावजूद विषमता की खाइयों की गहराइयां कम नहीं हो रहीं। बड़े-बूढ़ों से यह बात हम अक्सर सुनते रहते हैं कि आज़ादी पा लेने के बावजूद देश में समानता का वह सपना कहीं पूरा होते नहीं दिखता जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी देखा करते थे। यह एक सच्चाई अपने आप में बहुत कुछ कह देती है कि आज देश की आबादी के दस प्रतिशत ऊपरी हिस्से के पास देश की राष्ट्रीय संपत्ति का 77 प्रतिशत हिस्सा है!

आज जबकि हम अपनी आज़ादी के 78वें साल में दुनिया की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनने की ओर तेज़ी से बढ़ने के दावे कर रहे हैं, करोड़ों को गरीबी रेखा से उबारने की दुहाई दे रहे हैं, दुनिया की सबसे तेज़ी से सुधरती अर्थव्यवस्था होने का दम भर रहे हैं, स्वयं को विश्वगुरु मान रहे हैं तो यह सवाल उठना ही चाहिए कि देश की 80 प्रतिशत आबादी को सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रतिमाह 5 किलो अनाज पर जीवन-यापन क्यों करना पड़ रहा है? सरकारी मदद को भीख कहना अच्छा नहीं लगता है, पर हकीकत है- इससे भी तो इन्कार नहीं किया जा सकता।

बरसों पहले भारत की संसद में उठा तीन आने और तेरह आने वाला सवाल एक तरह से आज भी मुंह बाये हमारे सामने खड़ा है। देश की आर्थिक स्थिति पर बोलते हुए समाजवादी विचारक और नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुनौती दी थी कि वे इस स्थापना को गलत साबित करके बतायें कि देश के 27 करोड़ लोग तीन आने से भी कम पैसे में अपना जीवन-यापन करने के लिए विवश हैं। तब रुपये में सोलह आने हुआ करते थे और देश की आबादी भी 50-55 करोड़ थी। अपने उस भाषण में डॉ. लोहिया ने देश की संसद में कहा था, 'देश के प्रधानमंत्री पर प्रतिदिन पच्चीस हज़ार रुपये खर्च होते हैं! जबकि, देश का आम नागरिक प्रतिदिन तीन आने में अपना काम चलाने के लिए बाध्य है।' ज्ञातव्य है कि तब प्रधानमंत्री नेहरू ने डॉ. लोहिया की इस स्थापना को ग़लत तो कहा था, पर उन पर देशद्रोही होने का आरोप नहीं लगाया था।

आज़ादी की लड़ाई के दौरान स्वराज में मजदूर के भूखा सोने की बात कहने वाले की आलोचना तब भी होती थी, पर उन्हें देशद्रोही नहीं समझा जाता था। आज हम आज़ाद हैं, और आज़ादी का तकाज़ा है कि हम सतत्‌ सावधान रहने की शर्त को पूरा करने वाले नागरिक सिद्ध हों। नागरिक की जागरूकता स्वतंत्र देश की सार्थकता की पहली शर्त है। आज जबकि हम आज़ादी की 78वीं सालगिरह मनाए जा रहे हैं, हममें से हर एक को अपने आप से यह पूछना होगा कि सतत्‌ जागरूकता की इस कसौटी पर हम कितना सफल सिद्ध होते हैं? पूछना तो हमें अपने आप से यह भी है कि क्या वह पूरी आज़ादी हमने पा ली है जिसकी शपथ 95वें साल पहले हमने रावी नदी के तट पर ली थी?

यह पूरी आज़ादी की शपथ देश ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ली थी। इस पूरी आज़ादी का मतलब सिर्फ अपना शासन नहीं था। पूरी आज़ादी का मतलब था वह सोच जो हर नागरिक को खुली हवा में सांस लेते हुए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति का समान अवसर देती है।

स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर महंगी न समझने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, 'जब तक हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं, हम गुलाम ही हैं।' आज बापू के इन शब्दों को सही अर्थों में समझने की आवश्यकता है। पूरी आज़ादी का मतलब है समान अधिकारों और समान अवसरों के साथ जी पाना। क्या ऐसी स्थिति है हमारे देश में? आज़ादी की लड़ाई के दौरान जिस तरह राहत की बात कवि कर रहा था, क्या सचमुच हमने वह राहत पा ली है? हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्र भारत में एक ऐसे मानव-समाज की कल्पना की थी जिसमें हर नागरिक को समान अधिकारों के साथ जीने का अधिकार भी मिलेगा और अवसर भी। उस स्वतंत्रता में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। स्वतंत्र भारत में समानता का मतलब वह व्यवस्था होगी जिसमें झोपड़ी कुछ ऊंची होगी, महल कुछ नीचा। जाति और वर्ण के आधार पर किसी को नीचा या ऊंचा नहीं माना जायेगा। हमारे संविधान का आमुख हर नागरिक को न्याय पाने का पूरा अधिकार देता है। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की यह स्थितियां क्या हमने पा ली हैं?

एक सवाल और जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए वह यह है कि क्या हम सचमुच स्वतंत्रता और स्वराज का मतलब समझते हैं? स्वतंत्रता बंधन से मुक्ति का नाम है और स्वराज का मतलब है निज-शासन की युक्ति। स्वतंत्रता कुछ बंधन लाती है अपने साथ। बंधन अर्थात संयम। बंधन अर्थात मर्यादाओं में जीने की युक्ति। यह तो सब जानते हैं कि स्वराज का मतलब सत्ता का अपने अथवा अपनों के हाथ में आना है, पर हम में से कितने लोग यह समझते हैं कि स्वराज का मतलब यह भी है कि हम सत्ता के अनुचित उपयोग के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी अपने भीतर जगायें? अन्याय के विरोध का भाव जगाना ही पर्याप्त नहीं है, अन्याय के विरोध की क्षमता भी स्वतंत्र देश के हर नागरिक में होनी चाहिए। एक स्वतंत्र समाज का दायित्व बनता है कि वह ऐसी स्थितियां बनाये कि हर नागरिक में अन्याय का विरोध करने की क्षमता जगे।

पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी को तिरंगा फहराकर हम अपनी आज़ादी का उत्सव तो मना सकते हैं, पर इस उत्सव की सार्थकता तभी होगी जब देश का हर नागरिक वह जीवन जी सके, जिसमें आज़ादी अपने पूरे के साथ को पुष्पित-पल्लवित होगी। सच्चा और पूरा स्वतंत्र समाज वही है जिसमें हर रंग के फूल अपनी गंध बिखेर रहे हों, जहां जाति के आधार पर आदमी और आदमी के बीच की दूरी नहीं होगी। रावी के तट पर हमने पूरी आज़ादी पाने की शपथ ली थी, उस आज़ाद भारत में ऊंच-नीच का कोई भेद नहीं होना था, धर्म की दीवार नहीं होनी थी, पूरी आज़ादी वाले उस समाज में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, जहां धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है, जहां पूजा-स्थल मनुष्यता के धर्म को परिभाषित करते हैं। पूरी आज़ादी वाला वह समाज अभी बनाना है हमें। आर्थिक असमानता और सामाजिक विषमता की दीवारों-खाइयों को ढहाने-पाटने की आवश्यकता को अनुभव करके ही हम अपना बेहतर भारत बना सकते हैं। सच कहूं तो तभी जयहिंद कहने का अधिकार मिलेगा हमें।

अमेरिका-चीन से पाक का स्मार्ट गर्लफ्रेंड वाला प्रेम

आलोक पौराणिक

पाकिस्तान की मौज है इन दिनों, उस स्मार्ट गर्लफ्रेंड की तरह, जिसके दो चाहने वाले एक-दूसरे से कंपीटिशन में गर्लफ्रेंड की मौज करा रहे हैं। स्मार्ट गर्लफ्रेंड एक ब्वॉयफ्रेंड से कहती है दूसरा वाला तो महंगा वाला फोन दे गया, तुम महंगी ड्रेस दिलवा दो। फिर पहले वाले ब्वॉयफ्रेंड को यह महंगी ड्रेस दिखाकर कुछ और महंगा गिफ्ट मांगा जाता है। यही सब चल रहा है अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में।

पाकिस्तान कहता है अमेरिका से कि चीन तो पाकिस्तान में स्पेशल कॉरिडोर बना रहा है, करोड़ों लगा रहा है। आप भी कुछ लगाइये। अमेरिका करोड़ों देता है पाकिस्तान को, तो फिर चीन से कहा जाता है कि देखिये, उधर से इतने आ गये, आप भी कुछ लगाइये। इधर से लाओ, उधर से लाओ। स्मार्ट गर्लफ्रेंड सब तरफ से कमा लेती है।

पाकिस्तान शुरू से ही स्मार्ट गर्लफ्रेंड की तरह की लाइफ स्टाइल में रहा है। कभी उससे ले आओ, कभी इससे ले आओ। देने वाले भी जानते हैं कि यह संबंध नहीं सौदेबाजी है। पर जिंदगी में संबंध ही सब कुछ न होते, सौदेबाजी भी बहुत कुछ होती है। पाकिस्तान सौदेबाजी पर चल रहा है। चलता ही जा रहा है। कभी कुछ खुद करके नहीं कमाना। भीख का कटोरा, या स्मार्ट गर्लफ्रेंडबाजी इन्हीं तरकीबों से काम चल जाये तो कोई काम करने क्यों जाये।

अब दुनिया के हालात ऐसे हैं कि अमेरिका और चीन दोनों की जरूरत पाकिस्तान है। चीन को देर-सवेर पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बनाना है। पाकिस्तान का प्रयोग अमेरिका के लिए मौके मौके पर आता रहता है। अभी ट्रंप को भारत पर दबाव बनाना है, तो पाकिस्तान के आर्मी जनरल को लंच डिनर खिलाना है। ट्रंप ने कुछ साल पहले कहा था कि पाकिस्तान उनके डालर खा जाता है। अब ट्रंप खुद डालर खिला रहे हैं। वक्त बदला या नहीं बदला, पर ट्रंप की प्राथमिकताएं बदल गयीं। ट्रंप स्मार्ट बंदे हैं, पुरानी बातें भूल जाते हैं। पर पाकिस्तानियों को कई बार दिक्कत हो जाती है।

पाकिस्तान अब अपमान और मान से ऊपर उठ गया है। भीख मांगने का एक बहुत खराब असर यह होता है कि बंदे का आत्मसम्मान मर जाता है। ट्रंप ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत अर्थव्यवस्था है। ट्रंप को मृत आइटमों से डील करना आता है, तो ट्रंप पाकिस्तान से डील कर लेंगे। आफत चीन की है उस बर्बाद प्रेमी जैसी, जिसने इतने रुपये खर्च किये, इतनी जान लगायी और फिर उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड कहीं और चली जा रही है।

यह सवाल इज्जतदार देशों के लिए तो सटीक है। पर पाकिस्तान तो इसी तरह से चला है सत्तर से ज्यादा साल हो गये। अब पाकिस्तान क्या सुधरेगा। और सुधरने की कोशिश करे भी तो पुराने यार सुधरने न देंगे। पुराने कर्म आगे आते ही हैं।

घरेलू मांग की मजबूती से होगा मुकाबला

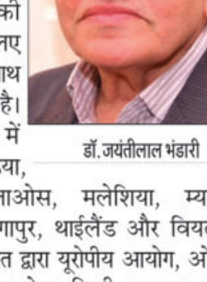

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में प्रकाशित मॉर्गन स्टैनली रिसर्च के एक विश्लेषण में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा भारत से निर्यात पर 50 फीसदी टैरिफ लागू किए जाने से विकास दर घटकर 6 फीसदी तक सिमट सकती है। हकीकत है कि मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र की ताकत के दम पर भारत अमेरिकी टैरिफ के दबाव को झेल लेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू वृद्धि को सहारा देने के लिए नीतिगत समर्थन बढ़ाया जाना जरूरी होगा। वस्तुतः वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से अमेरिका को कुल 86.5 अरब डॉलर का निर्यात हुआ, जो जीडीपी का 2.2 फीसदी है। ट्रंप टैरिफ की वजह से भारत के वस्तु निर्यात में करीब 30 अरब डॉलर की कमी आने की आशंका रहेगी। ऐसे में अमेरिका को निर्यात बाधित होने से भारत के द्वारा निर्यात और विकास दर बढ़ाने के लिए जहां घरेलू खपत बढ़ाने पर जोर देना होगा, वहीं निर्यात के नए बाजार तलाशने की रणनीति पर भी आगे बढ़ना होगा।

हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। यह भी कहा गया है कि भारत की विकास दर वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर से दो गुना से भी अधिक रहने का अनुमान है। इसी तरह दुनिया की प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में घरेलू खपत में सुधार, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, बेहतर मानसून, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, महंगाई में कमी, सस्ते कर्ज और अन्य सेक्टरों में सकारात्मक संकेतों के चलते इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 6.4 प्रतिशत के स्तर पर होगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योगमंत्री ने लोकसभा में कहा कि वैश्विक संस्थाएं भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का उज्ज्वल केंद्र मानती हैं। अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाए गए हैं, उनके मद्देनजर सरकार किसान, निर्यातकों और उद्योगों के हितों की रक्षा करेगी। अर्थ विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेज विकास के लिए आर्थिक, वित्तीय, श्रम और कृषि सुधारों को तेजी से लागू करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ना भी जरूरी है।

गौरतलब है कि हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई घटने से भी घरेलू बाजार में खपत को बढ़ावा मिल रहा है। सस्ते कर्ज से उद्योग-कारोबार में भारी उत्साह है। कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, मानसून की अच्छी प्रगति, पर्याप्त जलाशय स्तर और मजबूत खरीफ बुवाई का सुकूनदेह परिदृश्य दिखाई दे रहा है। निःसंदेह, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे बड़ा लोकतंत्र, स्टार्टअप्स, इनोवेशन और रिसर्च का इकोसिस्टम, सबसे तेजी से बढ़ता बाजार और विनिर्माण सेवा क्षेत्र की ऊंचाइयां ऐसी शक्तियां हैं, जो दुनिया के देशों को भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत में खुदरा महंगाई दर जून, 2025 में घटकर 2.1 प्रतिशत पर आ गई है।

जहां महंगाई में तेज गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है, वहीं भारत में सस्ते कर्ज से भी घरेलू उपचार में खपत और आर्थिक रफ्तार बढ़ेगी। विगत 6 जून को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए रेपो रेट में 50 आधार अंकों यानी 0.50 प्रतिशत की कटौती का ऐलान किया है। इस वर्ष 2025 में फरवरी से अब तक लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती हुई है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में भी एक प्रतिशत की बड़ी कटौती करते हुए इसे तीन प्रतिशत के स्तर पर ला दिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और सीआरआर में बड़ी कटौती करके तेज विकास की जरूरत और महंगाई के बीच बुद्धिमतापूर्ण समीकरण स्थापित किया है।

यह बात महत्वपूर्ण है कि रिकॉर्ड कृषि उत्पादन और अच्छा मानसून भी अर्थव्यवस्था की गतिशीलता और घरेलू खपत बढ़ने के मद्देनजर सुकूनदेह हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 2024-25 फसल वर्ष के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन 35.39 करोड़ टन होगा। इस समय वैश्विक व्यापार और वैश्विक निर्यात में कमी आ रही है, तब भारत के द्विपक्षीय और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के दम पर भारत के निर्यात और निवेश बढ़ रहे है।

निश्चित रूप से भारत के मुक्त व्यापार समझौते भारत की वैश्विक व्यापार उपस्थिति को नया रूप देते दिखाई दे रहे हैं। भारत द्वारा यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ किए गए एफटीए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत को यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए से मजबूत लाभ हुआ है। यूएई के साथ, पिछले चार-पांच वर्षों में सेवाओं का निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में 10 जुलाई को भारत में स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिस्साफी ने कहा कि भारत और 4 सदस्य देशों आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन वाले यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) के बीच व्यापार समझौता अक्तूबर, 2025 से लागू हो जाएगा। इन सबके साथ-साथ इन दिनों भारत-आसियान के बीच मौजूदा व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए आसियान के साथ चर्चा जारी है। आसियान में ब्रनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। भारत द्वारा यूरोपीय आयोग, ओमान, कतर, न्यूजीलैंड, पेरू, चिली, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इस्राइल, भारत गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य देशों के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देने की डगर पर आगे बढ़ रहा है।

अब भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया के जीवंत आर्थिक क्षेत्र से फिर से जुड़ना होगा। इन सबके साथ-साथ भारत को व्यापक एवं प्रगतिशील प्रशांत पार साझेदारी (सीपीटीपी) का हिस्सा बनने के लिए आगे बढ़ना होगा। पूरी दुनिया में भारत के सेवा निर्यात को तेज रफ्तार से बढ़ाना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होगा भव्य आयोजन

भोपाल।

दुनिया के 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर 21 जून 2025 को आयोजन की तैयारी पर मध्य प्रदेश के सीएम यादव ने बोला है कि यपग शरीर के रोग को खत्म करके इसे विकार मुक्त करता है, हर किसी को स्वस्थ काया के लिए रोजाना योग करने की आदत डालना चाहिए, पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर पुरातन योग की पद्धति को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल गई है, इसलिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 21 जून 2025 के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है।

बारिश से बचने के लिए किए गए खास बंदोबस्त

खबरों का कहना है कि सीएम यादव ने इस बारें में बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला है, इतना ही नहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी लगाया है लकी इस दिन बारिश होने की उम्मीद अधिक है और इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के आयोजन वाले स्थल को चुनने के आदेश जारी कर दिए है, इतना ही नहीं जगह ऐसी हो जो कि ऊपर की तरफ से पूरी तरह से कवर्ड हो, उसमे अधिकतर लोग भाग लें सके।

अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे बोला है कि योग अभ्यास में सबकी सहभागिता होना अच्छी बात है, इतना ही नहीं इसमें बच्चे ही नहीं, युवा, बुजुर्ग, महिला भी हिस्सा लें, योग अभ्यास कार्यक्रम की सभी समुचित एवं सुनियोजित तैयारी भी की जानी चाहिए। योग अभ्यास वाले स्थल पर पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, आयोजन वाले स्थान पर पार्किंग की फुल व्यवस्था की जाना चाहिए, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी बोला है कि योगाभ्यास कार्यक्रम यथासंभव स्कूल, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज या ऐसी अन्य शिक्षण संस्थाओं के कवर्ड कैम्पस में ही आयोजित किया जाएं।

क्या है इस वर्ष की थीम?

दरअसल इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंटरनेशनल योगा डे की थीम ''योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ'' रखी गई है, इतना ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सुबह 6 बेस 6 बजकर 20 मिनट तक स्थानीय कार्यक्रम और जनप्रतिनिधियों के उद्बोधन होने वाला है। प्रातः 6:20 से लेकर 6;30 बजे तक सीएम यादव के उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया जाने वाला है, वहीं प्रातः 6:30 से 7:00 बजे तक विशाखापट्टम से पीएम मोदी नरेंद्र के उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया जाने वाला है, वहीं प्रातः 7:00 से 7;45 बजे तक सामान्य योग प्रोटोकॉल का सामूहिक योग अभ्यास सभी लोगों द्वारा किया जाने वाला है, स्टेट लेवल कार्यक्रम में सीएम यादव मुख्य अतिथि होने वाले है।

इस बारें में प्रमुख सचिव ने जानकारी दी है कि जिले के स्तर पर कार्यक्रम मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक के मुख्य आतिथ्य में जिला मुख्यालयों में किया जाने वाला है, इतना ही नहीं सारे गवर्नमेंट अधिकारीयों के योग अभ्यास की भागेदारी को तय करने के लिए शासकीय मंत्रालयों की अधीनस्थ संस्थाओं में एवं स्कूल में भी योग अभ्यास का कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मध्य प्रदेश के 10 प्रमुख स्थल शामिल

खबरें है कि खजुराहो (पश्चिमी मंदिर समूह में), भीमबेटका (गुफाओं पार्किंग क्षेत्र के सामने), अमरकंटक (मंदिर समूह में), भोपाल (कमलापति पैलेस में), ग्वालियर (मानसिंह महल के पास), ओरछा, सांची (स्तूप नंबर एक के पास, लाइट एंड साउंड शो क्षेत्र में), माण्डु (जहाज महल के सामने) तथा महेश्वर में भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है।

अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति 16 को

माही की गूंज, खवासा।

बस स्टैंड स्थित गांव के प्राचीनतम और चमत्कारिक हनुमान मंदिर में पिछले 50 वर्षों से श्रावण के पवित्र माह में अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है। 50वें वर्ष में प्रथम दिन विशाल कलश यात्रा के साथ रामायण जी की स्थापना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पवित्र ग्रंथ को बारी-बारी से अपने सिर पर उठाकर श्रद्धालु चल रहे थे।

पिछले एक माह से प्रतिदिन एक-एक घंटे रामायण जी का वाचन अलग-अलग श्रद्धालुओं द्वारा किया जा रहा था और प्रतिदिन पाठ पूर्ण होने पर आरती की जाती थी। अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति जन्माष्टमी के अवसर पर 16 अगस्त को की जाएगी, जिसमें एक महायज्ञ का आयोजन भी होगा।

यज्ञमान का चयन गोटी डालकर किया गया, जिसमें मूलचंद चौहान मुख्य यजमान रहेंगे। इसके साथ ही हनुमान जी को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे और बैंड-बाजों के साथ विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी।

अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए 4 वाहन जब्त

माही की गूंज, अलीराजपुर।

जिला खनिज अधिकारी सतीश नागले ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर के समक्ष लगातार प्राप्त हो रहे खनिजों के परिवहन के संबंध में शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर डॉ बेडेकर के निर्देशान के पालन में खनिज विभाग द्वारा जिले में हो रहे अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु 13 अगस्त 2025 को कुल 04 वाहन में अवैध खनिज रेत ओवरलोड के परिवहन करते पाया गया है। जिसमें से 02 वाहनों को कलेक्टर परिसर में खडे किये गये एवं 02 वाहन को थाना बोरी की अभिरक्षा में रखें गये है। कार्यवाही के दौरान खनिज निरीक्षक शेलेश किराडे वाहन चालक मानसिंह सोलंकी मौके पर उपस्थित रहें। वाहनों के प्रकरणों को पंजीबद्ध कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगें।

प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्री विघ्नहरा पार्श्वनाथ मंदिर में हुआ जिनालय शुद्धिकरण

माही की गूंज, मंदसौर।

मंदसौर में नवरत्न परिवार एवं मालवा महासंघ के पावन तत्वावधान में वर्ष 2011 से प्रारंभ हुआ जिनालय शुद्धिकरण महाअभियान रविवार को नगर के खिलचीपुरा स्थिति तीर्थ स्थान श्री विघ्नहरा पार्श्वनाथ मंदिर में अत्यंत श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ सम्पन्न किया गया।

आचार्यों की दिव्य प्रेरणा और आशीर्वाद से, नवरत्न परिवार एवं मालवा श्री संघ के संयुक्त संकल्प के तहत, यह दिव्य शुद्धिकरण कार्य संपूर्ण भारत के 13 राज्यों में, एक ही दिन एवं एक ही समय पर सम्पन्न होता है।

जिनालय शुद्धिकरण समिति के सीए प्रतिक डोसी, संदीप धींग ने बताया कि जिनालय शुद्धिकरण एक प्रकार का जैन धर्म में एक अनुष्ठान है जिसका अर्थ है जैन मंदिरों एवं मूर्तियां को पवित्र और शुद्ध करना यह एक विशेष प्रक्रिया है जिसके द्वारा जिनालय में नकारात्मक ऊर्जा एवं अशुद्धियों से मुक्त किया जाता है जिससे वह पूजा एवं ज्ञान के लिए उपयुक्त स्थान बन जाते हैं इसके अलावा मंदिरों की साफ सफाई पात्रों की साफ सफाई शुद्धता यह सब जिनालय शुद्धिकरण के दौरान किए जाते हैं।

नवरत्न परिवार की ओर से ही पहुंचाए जाते हैं शुद्धिकरण के किट

प्रत्येक जिले एवं कस्बे में नवरत्न परिवार की शाखाएं बनी हुई है जो इस जिनालय शुद्धिकरण में समाजजनों के साथ इस कार्य को करते हैं नवरत्न परिवार एवं मालवा महासंघ के पदाधिकारी जिनालय शुद्धिकरण की किट जिसमें विशेष प्रकार की औषधियां पात्र साफ सफाई के साधन कुछ मंदिर उपयोगी सामग्रियां आदि से एक किट तैयार की जाती है जो निशुल्क सभी श्री संघों में पहुंचाई जाती हैं जिसमें मालवा महासंघ एवं नवरत्न परिवार हर शाखों में पहुंचकर समाज जनों को यह किट वितरित करते हैं।

दाऊदी बोहरा समाज की मदद से सरकारी अस्पताल में हो रही मुफ्त आर्थो सर्जरी

माही की गूंज, रतलाम।

सालभर पहले, जब सरकारी अस्पताल में एक्सीडेंट के मरीजों को सर्जरी के लिए रतलाम या इंदौर भेजा जाता था, वहां हड्डी संबंधी सर्जरी के लिए हजारों रुपये खर्च होते थे। लेकिन अब दाऊदी बोहरा समाज की मदद से अस्पताल में हड्डी संबंधी सर्जरी मुफ्त की जा रही है।

समाज से प्राप्त करीब 10 लाख रुपये के आर्थोपेडिक उपकरणों की वजह से अब तक 50 से अधिक मरीजों की सफल सर्जरी हो चुकी है, जिससे 8 लाख रुपये की बचत हुई है।

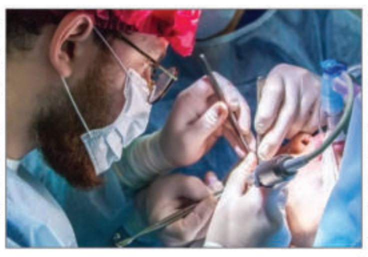

अस्पताल में हर महीने 25 से अधिक सड़क हादसे और दुर्घटनाओं के मामले आते हैं, जिनमें से 15-20 मरीजों को हड्डी के फैक्चर होते हैं। पहले मरीजों को कच्चा पट्टा बांधकर रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब आर्थो सर्जन डॉ. अजयसिंह राठौर के नेतृत्व में सर्जरी की जा रही है।

उदाहरण के तौर पर, राकेश नामक मरीज को 14 मार्च को बाइक एक्सीडेंट में पैर की हड्डी टूटने पर अस्पताल में सर्जरी की गई। पहले इस ऑपरेशन में 25 हजार रुपये खर्च होने थे, लेकिन अब यही ऑपरेशन मुफ्त हो गया। इसी तरह, शिवानी सिसोदिया, जो साइकिल से गिरने के बाद हाथ में फैक्चर हो गया था, उसकी सर्जरी भी सरकारी अस्पताल में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के की गई।

अब अस्पताल में हर महीने 4 से ज्यादा सर्जरी हो रही हैं, और मरीजों का समय और पैसा दोनों बच रहा है। समाजजन ने भविष्य में और मदद करने की बात भी कही है, जिससे अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

पीला मोजेक रोग की रोकथाम के लिए किसान भाई इमिडाक्लोप्राइड या थायोमेथोक्जाम कीटनाशक का छिडकाव करें

माही की गूंज, अलीराजपुर। कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने जिले के कृषकों के लिए एडवाइजरी जारी कर बताया कि वर्तमान समय में वर्षा की कमी से सोयाबीन उड़द मूंग मक्का फसलों में कीट एवं बीमारियों की ज्यादा समस्या देखी जा रही है जो लगातार बढ़ रही है। सोयाबीन मूंग उड़द फसलों में सफेद मक्खी का बहुत ज्यादा प्रकोप देखा गया है जिसके फलस्वरूप इन फसलों में पीला मोजेक रोग का प्रकोप भी बढ़ रहा है , पीला मोजेक रोग की रोकथाम के लिए किसान भाई जितना जल्दी हो सके सफेद मक्खी का नियंत्रण करें क्योंकि पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी के माध्यम से ही फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्राइड या थायोमेथोक्जाम कीटनाशक का प्रति स्प्रे पंप 8-10 ग्राम मिलाकर छिड़काव करें । मक्का फसल में तनाव भेदक कीट के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशक का 10 ग्राम प्रति स्प्रे पंप की दर से छिड़काव करें। इस प्रकोप से बचाव के लिए कलेक?टर डॉ बेडेकर ने कृषि विज्ञान केन्द्र डॉ राकेश यादव को वास?तु स्थित एवं निरीक्षण करने के निर्देश दिए , डॉ यादव द्वारा ग्राम राजावाट, खरपई, लक्ष्मणी, मायला, भंवरी आदि गांवों का भ्रमण किया कृषकों को उक्त छिडकाव करने के लिए प्रेरित किया गया। उक्त जानकारी केवीके द्वारा दी गई।

तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा का कर सकते है आवेदन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

संयुक्त कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह बघेल ने बताया कि, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यात्रा अन्तर्गत 28 अगस?त 2025 से 02 सितम?बर 2025 तक तिरूपति यात्रा हेतु जिला अलीराजपुर से कुल 200 बर्थ आवंटित की गई है , जिले के इच?छुक यात्री आवेदन नजदि?की जनपद पंचायत तथा तहसील कर्यालय में आवेदन कर सकते है। 60 वर्ष या उससे अधिक के नागरिकगण आवेदन कर सकते है।

गांव में मिले दुर्लभ बीमारी जीबीएस के चार मामले, मचा हड़कंप

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के मुलतानपुरा गांव में गुलियन बेरी सिंड्रोम (जीबीएस) नामक एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी बीमारी के चार मामलों की पुष्टि हुई है। यह जानकारी जिला कलेक्टर अदिति गर्ग ने दी।

कलेक्टर ने बताया कि, अब तक गांव से जीबीएस के सात संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें से चार मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन ने गांव में जांच और सर्वे टीमों को तैनात कर दिया है, जो घर-घर जाकर यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कहीं अन्य लोग भी इस बीमारी से पीड़ित तो नहीं हैं।

अदिति गर्ग ने बताया कि, कुछ मरीजों का इलाज मंदसौर के बाहर अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहरों में भी चल रहा है। ऐसे मरीजों की चिकित्सकीय रिपोर्ट की जांच की जा रही है ताकि यह समझा जा सके कि संक्रमण किस कारण फैला। जिला अस्पताल और सर्वे के प्रभारी डॉ. शुभम सिलावट ने बताया कि जीबीएस से पीड़ित व्यक्ति में डायरिया, बुखार, मांसपेशियों में कमजोरी और झनझनाहट जैसे प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यह बीमारी दुर्लभ जरूर है, लेकिन किसी को भी हो सकती है और आमतौर पर किसी संक्रमण के बाद ही विकसित होती है।

इस बीमारी में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) खुद ही नसों पर हमला करने लगती है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और कुछ मामलों में लकवे की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र के पुणे जिले में जीबीएस के करीब 200 मामले सामने आए थे, साथ ही मुंबई सहित अन्य जगहों पर भी कुछ मामले दर्ज किए गए थे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति इन लक्षणों से पीड़ित हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और लापरवाही न बरतें।

कंबल केंद्र में स्व-सहायता समूहों द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित

माही की गूंज, मंदसौर।

म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत मन्दसौर प्रबंधक दिनेश कुमार रैकवार द्वारा बताया गया कि, म.प्र. डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत के तत्वावधान में संचालित स्व-सहायता समूहों की दीदियों द्वारा हस्तनिर्मित एवं स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है यह प्रदर्शनी कंबल केंद्र, मंदसौर में आयोजित की जा रही है, जहाँ विभिन्न स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित वस्त्र, हस्तशिल्प सामग्री, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ एवं अन्य नवीन और स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये सभी उत्पाद बिक्री हेतु भी उपलब्ध हैं। जिससे स्थानीय महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री कैलाश चावला ने प्रदर्शनी स्थल पर पहुँचकर विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और दीदियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जिला प्रशासन एवं आयोजन समिति द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वह अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शनी स्थल पर पहुँचें, स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं तथा ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भरता के प्रयासों को प्रोत्साहन दें।

पंचायत विकास सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतें हुई सम्मानित

माही की गूंज, मंदसौर।

पंचायत उन्नति सूचकांक वर्ष 2022-23 का विमोचन एवं प्रचार-प्रसार के जिला जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंदसौर जिला पंचायत में किया गया। कार्यक्रम में पंचायत एवं जिला विकास सूचकांक के 9 विषयों पर जिले की अलग-अलग ग्राम पंचायतों का चयन किया गया।

जिसमें सशक्त पंचायत सतत् विकास की अवधारणा के साथ पंचायतों को सशक्त बनाने, उनके कामकाज को पारदर्शी और कुशल बनाने के किए गए कार्य के आधार पर जिले की ग्राम पंचायत को पंचायत विकास सूचकांक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत सेमली कंकड़ प्रथम पुरस्कार राशि 11 हजार रुपये , ग्राम पंचायत भरतपुरा द्वितीय पुरस्कार राशि 7 हजार 100 रुपये, ग्राम पंचायत खजुरी गौड़ तृतीय पुरस्कार राशि 5 हजार 100 रुपये एवं बाकी सात ग्राम पंचायतों जैसे हरसोल, सेमली, सांडा अरनिया जटिया, लेडी कला,ऐरा, एवं अजयपुर को राशि 2 हजार 100 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही अन्य 10 चयनित ग्राम पंचायत जग्गाखेड़ी (नाहरगढ़), बोरदा, लिम्बवास,ओसारा, बाजखेड़ी, कोहला, धंधेडा, लौटखेड़ी, कोटड़ा बहादुर एवं निमथुर को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए एवं सभी का टीएमपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया।

सरदारपुर को मिली विकास और स्वास्थ्य सेवाओं की सौगातें

माही की गूंज, धार।

सरदारपुर विकास के नए अध्याय का साक्षी बना, जब प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का लोकार्पण करते हुए क्षेत्र को स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी सौगात दी। लोकार्पण समारोह में मंत्री ने कहा कि अस्पताल की हर जरूरत को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा और किसी भी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने ऑनरेरी सेवा देने वाले डॉक्टरों से अस्पताल में जुड़कर जनसेवा का आग्रह किया और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को आवश्यकतानुसार तकनीशियन नियुक्त करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं में सख्ती, पारदर्शिता और विस्तार का वादा

मंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों को चेतावनी दी कि वे बाज़ार की दवाएं न लिखें। अस्पताल में निशुल्क दवा प्रदाय के लिए पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, और यदि किसी दवा की कमी हो तो अस्पताल प्रशासन सीधे कलेक्टर से संपर्क करे। उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाएं जुटाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जरूरत पड़ने पर एक और अस्पताल भी बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना को जनहितकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब इलाज से वंचित न रहे। लोगों से इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक फैलाने का आह्वान किया।

विकास कार्यों का सुनहरा अध्याय

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि खरमोर अभयारण्य में अधिग्रहित 14 गांवों की भूमि अब किसानों को मालिकाना हक के साथ वापस मिल गई है। साथ ही, क्षेत्र को 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़कों की भी सौगात दी गई। बिजली और सड़क उत्पादन में वजीफ़ मूल्य देने की जानकारी देते हुए उन्होंने हरियाली को समय की जरूरत बताया और प्रेरित किया कि हर व्यक्ति हर साल अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाए।

महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि हर बहन ÷लखपति बहनाओं÷ की सूची में शामिल हो, और सरकार ने इसके लिए कई योजनाएं लागू की हैं।

18 ग्राम पंचायत भवनों का भूमि पूजन

प्रभारी मंत्री ने जनपद पंचायत सरदारपुर में 18 नवीन ग्राम पंचायत भवनों (अटल सेवा सदन) का भूमि पूजन किया। प्रत्येक भवन पर 37.50 लाख रुपये की लागत आएगी, जो ग्रामीण प्रशासन और सेवा वितरण को सुदृढ़ करेगा।

कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। मंच से जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेढ़ा, विधायक प्रताप ग्रेवाल, निलेश भारती, चंचल पाटीदार और वेलसिंह भूरिया ने भी क्षेत्रवासियों को संबोधित किया।

अंत में, मंत्री ने उपस्थित जनसमुदाय को स्वच्छता और जल संरक्षण का संकल्प दिलाया और कार्यक्रम के बाद उत्साहपूर्वक तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए।कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एसपी मनोज कुमार सिंह,सीईओ अभिषेक चौधरी भी उपस्थित थे।

गैंगरेप-हत्याः बेटा बना सरकारी गवाह, पिता के खिलाफ दिया बयान

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा जिले के खालवा थाना क्षेत्र में 24 मई 2025 को हुई आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की जघन्य वारदात के मामले में 11 अगस्त से न्यायिक कार्यवाही शुरू हो गई है। इस घटना में शराब के नशे में धुत दो युवकों ने हैवानियत की हदें पार कर दीं, जिसके बाद पीड़िता की मौत हो गई थी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों हरिराम और सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। करीब चार महीने की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में 400 पन्नों का विस्तृत चालान पेश किया। इस मामले में 32 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं, जिनमें मुख्य आरोपी का बेटा भी सरकारी गवाह के रूप में शामिल है।

पुलिस की जांच में घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, खटिया और खून लगी गोदड़ी, तथा मृतका और आरोपियों के कपड़े, बाल और नाखून के नमूनों की डीएनए व फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे चार अहम सबूत सामने आए हैं। फुटेज में पीड़िता, सुनील और हरिराम साथ दिखे। प्रत्यक्षदर्शियों में आरोपी की मां, बेटा, मृतका के रिश्तेदार, पड़ोसी, पुलिसकर्मी और डॉक्टर शामिल हैं। वारदात में प्रयुक्त खटिया, खून से सनी गोदड़ी, खटिया की नवाड़ और बाड़े की मिट्टी के नमूने जब्त किए गए।

सुनील | हरि

आरोपी हरिराम ने बयान में कहा कि महिला के साथ आपसी सहमति से संबंध बने। उसने स्वीकार किया कि नशे में उसने महिला के निजी अंग में हाथ डाला, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं, सुनील ने कहा कि वह केवल शराब पीकर चला गया और वारदात में शामिल नहीं हुआ। आरोपी हरिराम के बेटे ने अदालत में बयान दिया कि 23 मई की रात उसके घर के आंगन में पीड़िता, हरिराम और सुनील शराब पी रहे थे। दादी ने उन्हें भगाया, सुनील चला गया, लेकिन हरिराम और पीड़िता वहीं रहे। बाद में पिता ने उसे रसोई में बुलाकर खून से लथपथ बेहोश पड़ी पीड़िता दिखाई और किसी को न बताने की हिदायत दी।

पीड़िता की बहू के अनुसार, घटना वाले दिन शाम को सास रिश्तेदारों को खेत छोड़ने गई थीं और वापस नहीं लौटीं। अगली सुबह आरोपी हरिराम की मां ने बताया कि सास उनके घर के पास पड़ी हैं। देखने पर वह खून से लथपथ बेहोश मिलीं। होश में आने पर उन्होंने बताया कि हरिराम और सुनील ने उनके साथ दुष्कर्म किया।

फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉ. सीमा ने अदालत में कहा कि अत्यधिक शराब पिलाए जाने से महिला अर्द्धचेतन अवस्था में थी और प्रतिरोध करने में असमर्थ हो सकती थी। नाखूनों से बलपूर्वक चोट लगने पर गहरा कटाव संभव है, जिससे आंत बाहर आ सकती है और अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु हो सकती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जुलाई में चालान पेश करने के बाद 11 अगस्त से सुनवाई शुरू हो गई है और साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

घटना के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया पीड़िता के घर पहुंचे और राहुल गांधी ने फोन पर पीड़िता के बेटे से बात की। कांग्रेस ने तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीड़िता के गांव भेजा।

भाजपा की सुधा महाजन बनीं नगर परिषद अध्यक्ष

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन जिले की भीकनगांव नगर परिषद में बुधवार को हुए अध्यक्ष चुनाव में भाजपा की सुधा विजय महाजन ने जीत दर्ज की। यह पद पिछड़ा वर्ग आरक्षित महिला के लिए था। सुधा महाजन को 10 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ऋतु वर्मा को 5 मत प्राप्त हुए।

अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया सुबह 11 बजे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय परिसर में शुरू हुई। भाजपा पर्यवेक्षक सुभाष कोठारी ने रायशुमारी में सर्वसम्मति से सुधा महाजन का नाम प्रस्तावित किया, वहीं कांग्रेस ने ऋतु महेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया।

नगर परिषद में भाजपा के 9 और कांग्रेस के 6 पार्षद हैं। चुनाव में सुधा महाजन को कांग्रेस का भी एक मत मिला। पिछली बार क्रॉस वोटिंग के कारण बहुमत होने के बावजूद भाजपा अध्यक्ष पद पर काबिज नहीं हो पाई थी।

फरवरी 2022 में वार्ड 5 से निर्दलीय पूनम जायसवाल पार्षद चुनी गई थीं और कांग्रेस के समर्थन से अध्यक्ष बनी थीं। नामांकन में आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं देने और दो जगह मतदाता सूची में नाम होने के कारण न्यायालय ने उनका पद शून्य घोषित कर दिया था।

पद खाली होने पर सुधा महाजन को प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद वार्ड 5 के उपचुनाव में भाजपा के कमलेश कौशल ने कांग्रेस समर्थित पूनम जायसवाल को हराया, जिससे भाजपा की परिषद में संख्या बढ़ गई। निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम आकांक्षा अग्रवाल ने जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई।

बाल संप्रेषण गृह अधीक्षक रिश्वत लेते पकड़ा गया

माही की गूंज, खंडवा।

मंगलवार को बाल संप्रेषण गृह के अधीक्षक हरजिंदर सिंह अरोरा को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा। महिला रसोईया की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि अरोरा, महिला रसोईया से 2 से 4 हजार रुपये प्रतिमाह रिश्वत मांगता था, जबकि उसका वेतन मात्र 9 हजार रुपये मासिक था।

शिकायतकर्ता रसोईया ज्योति पाल ने बताया कि वह पिछले चार वर्षों से बाल संप्रेषण गृह में कार्यरत है और जून-जुलाई माह का वेतन उसे नहीं मिला था। जब अधीक्षक से संपर्क किया तो उसने दो माह का वेतन देने के एवज में 2 हजार रुपये प्रति माह रिश्वत की मांग की और पैसे न देने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी। परेशान होकर उसने इंदौर में पढ़ाई कर रही बेटी को यह बात बताई, जिसके बाद बेटी ने अपने मित्र के साथ लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई।

लोकायुक्त निरीक्षक आशुतोष मिठास ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपी और रसोईया की बातचीत का ऑडियो सत्यापित किया गया। इसके आधार पर आज अधीक्षक को रंगे हाथ दबोचा गया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम बाल संप्रेषण गृह के कार्यालय की अलमारी के ऊपर से बरामद की गई।

ज्योति पाल ने आगे बताया कि अरोरा का एक माह पहले ही खंडवा में पदस्थापन हुआ था, लेकिन इससे पहले भी वह यहां काम कर चुका था और तब भी वह वेतन में से 2 हजार रुपये प्रतिमाह रिश्वत लेता था। अरोरा के तबादले के बाद आए नए अधिकारी ने रिश्वत नहीं ली थी।

यह मामला महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार की गंभीर जांच का विषय बन गया है। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि छह वर्ष पहले भी हरजिंदर अरोरा पर महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक संचालक रहते हुए, कलेक्टर के नाम पर 50 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगा था। नवजीवन चिल्ड्रन्स संस्था की संचालक सिस्टर एमिली ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ यह शिकायत की थी, जिसके आधार पर इंदौर संभागायुक्त ने अरोरा को निलंबित किया था। शिकायत लोकायुक्त तक भी पहुंची थी, लेकिन जांच के दौरान अरोरा को क्लीन चिट मिल गई थी।

11 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद

माही की गूंज, बड़वानी।

पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस ने धार जिले के करवा बाग निवासी 19 वर्षीय संदीप उर्फ सक्षम बैरागी वैष्णव को बुधवार को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। आरोपी के पास से 6 लाख 19 हजार रुपये कीमत की मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की गई हैं।

पुलिस के अनुसार, शहर में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपी को पकड़ा। बरामद वाहनों में 7 मोटरसाइकिल और 4 स्कूटी शामिल हैं।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले शहर की कई दुकानों में काम कर चुका है और इस दौरान उसने क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी हासिल कर ली थी। इसके बाद उसने बड़वानी और आसपास के क्षेत्रों में कई वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया।

इस कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी दिनेशसिंह कुशवाह, उपनिरीक्षक राजीवसिंह ओसाल, शीलेंद्र परिहार, सायबर सेल के रितेश आचरी सहित पूरी टीम का योगदान रहा।

निकली शिव डोला यात्रा

माही की गूंज, सेंधवा।

मंगलवार को सेंधवा में हिंदू समाज सेवा समिति द्वारा सावन माह के उपलक्ष्य में शिव डोला यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान राजराजेश्वर महादेव की पालकी ने तीन किलोमीटर लंबी यात्रा लगभग पांच घंटे में पूरी की।

यात्रा में महाकाल मंदिर की प्रतिकृति, दूल्हे की बारात, नंदी गण, शिव-पार्वती और बाहुबली हनुमान दल की आकर्षक झांकियां शामिल थीं। कलाकारों ने जगह-जगह अपनी प्रस्तुतियां दीं और श्रद्धालुओं को 20 से अधिक स्थानों पर प्रसादी वितरित की गई। जहां-जहां पालकी रुकी, वहां महिला-पुरुषों ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे और कई स्थानों पर आतिशबाजी की गई।

शिव डोला पुराना बस स्टैंड से शुरू होकर, पुराना एबी रोड, गुरुद्वारा रोड, संत विनोबा मार्ग और राम बाजार होते हुए रात करीब 10 बजे मंदिर पहुंचा।

आयोजन में कमलाकर सोनी, शिरीष दुबे, अक्षय श्रीवास्तव, गणेश नरगांवने, कुश मित्तल और संतोष जाट मौजूद रहे। भाजपा नेता संजय यादव, मोहन जोशी और विकास आर्य भी शामिल हुए।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन सतर्क रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), तहसीलदार और शहर थाना प्रभारी मौजूद रहे। यात्रा मार्ग पर ड्रोन और बंद सर्किट कैमरों से निगरानी की गई। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष पुलिस बल तैनात किया गया और सोशल मीडिया पर भी विशेष टीम ने नजर रखी।

ट्रंप की तल्खी से उपजा वैश्विक असंतुलन

डोनॉल्ड ट्रंप के लिए पिछला हफ़्ता काफ़ी व्यस्त रहा। उन्होंने भारत के समक्ष टैरिफ़ रूपी विकट चुनौती बना डाली है, पहले लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ़ को बढ़ाकर दोगुणा यानि 50 प्रतिशत कर दिया। साथ ही उन्होंने भारत के साथ तमाम व्यापार वार्ताएं रद्द कर दी हैं। उन्होंने भारत को यह धमकी भी दी है कि यदि वह रूस से सस्ता तेल ख़रीदना जारी रखेगा, तो और कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने अमेरिका से कई भूटानी प्रवासियों को वापस भेजने का आदेश भी जारी किया है। उन्होंने एक बॉन्ड पेश किया है जिसके तहत कुछ श्रेणी के पर्यटकों को अमेरिकी वीज़ा पाने के लिए 5,000 से 15,000 डॉलर भरने होंगे। अमेरिकी कॉलेजों को उनका नया आदेश है कि वे दाखिले के इच्छुक आवेदकों के टेस्ट प्वाइंट औसत के अलावा नस्ल और लिंग संबंधी आंकड़े एकत्र करें।

आप पूछ सकते हैः ' अमेरिकी राष्ट्रपति को इतना गुस्सा क्यों आता है'? वह हर समय गुस्से में क्यों रहते हैं? हेप्पीनेस गुरु दीपक चोपड़ा इसका कारण ट्रंप की प्यार पाने की चाहत, यहां तक कि प्रशंसा की निरंतर और बेइंतहा भूख बताते हैं। हो सकता है कि वे सही हों। ट्रंप के आत्ममुग्धता भरे व्यवहार ने न केवल दुनिया को उलट-पुलट करके रख दिया, बल्कि ऐसा नाटकीय असर हुआ कि अमेरिका के साथ समझौते करने को देश कतारबद्ध खड़े हैं।

सिर्फ़ एक भारत ही अलग किस्म की प्रतिक्रिया दे रहा है। मोदी ने कहा है कि वे भारत के किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे और अमेरिका के सामने खड़े होने की कीमत चुकाने को तैयार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल आनन-फानन में कुछ दिन पहले मास्को पहुंचे, व्लादिमीर पुतिन को क्रेमलिन स्थित उनके आवास से बाहर लाकर हाथ में हाथ डाले दिखे और उनसे दिल्ली शीघ्र आने का सार्वजनिक वादा लिया। प्रधानमंत्री भी जल्द ही शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए चीन का दौरा करेंगे।

ऐसा लगता है कि पिछले एक हफ़्ते में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता, गुटनिरपेक्षता - इसे आप जो भी कहें - का मतलब पूरी तरह समझ लिया है। यह विचार कि बाहरी दुनिया के साथ व्यवहार करते समय भारत अपनी खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर रहेगा।

अगले कुछ महीने दिलचस्प होने वाले हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन नवंबर में होने की उम्मीद है अर्थात ट्रंप की भारत आने की बारी है। रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय वार्ता भी हो सकती है, जिसे भारत कुछ समय से टालता आया है क्योंकि वह अमेरिकियों को अनावश्यक रूप से नाराज़ नहीं करना चाहता था। मुख्य प्रश्न उठता है कि क्या एक नए शीत युद्ध की आशंका है। साथ ही, पिछले हफ़्ते विदेश नीति में 'हाथ जलने' से भारत ने कौन-सा बड़ा सबक सीखा है?

पिछले एक दशक से, मोदी अमेरिकियों को लगातार डोरे डालने में लगे हुए थे। जाहिर है, इसमें कुछ भी ग़लत नहीं - आधा पंजाब, जो पहले से ही अमेरिका-कनाडा जा बसा है, अमेरिका की अपार शक्ति को बख़ूबी समझता है, और उनकी भांति देश के बाकी हिस्सों से गए लोगों का एक बड़ा तबका भी, वह जिसे अभी भी ग्रीन कार्ड का बेसब्री से इंतजार है। यह बात भारतीय अभिजात्य वर्ग के लिए भी उतनी ही सच है जितनी उन अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली लोगों के लिए, जो अपनी संतान को बेहद समृद्धि और बेहतरीन जीवन की उम्मीद से भरपूर देशों में भेजने को अपनी संपत्ति तक बेच देते हैं।

लेकिन मोदी इससे भी कई कदम आगे बढ़ गए, निस्संदेह इस विश्वास के साथ कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र के साथ जुड़े रहने पर, उस गठबंधन के लाभ मिलेंगे - ठीक वैसे ही जैसा कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया था। सवाल पैदा होता है कि क्या भारत एक छोटे से मुल्क जापान - एक महान और अद्भुत देश - जैसा बनना चाहता है या खुद एक विलक्षण, सभ्यतागत शक्ति बनना चाहेगा। अमेरिका के साथ मौजूदा विवाद इस प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा वक्त है।

दरअसल, हाल के वर्षों में भारत की विदेश नीति ज़्यादा ही संशय में नज़र आई है। अमेरिका की तरफ असाधारण ध्यान उसी समय बना जब चीनी सैनिकों ने कोविड-19 के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर ली - जिसने पीएम मोदी और भारत दोनों को हैरान-परेशान कर दिया। इससे चीन-भारत संबंधों में भारी गिरावट आई। चार साल बाद, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के बीच बहुत बड़े अंतर ने पुनर्विचार करने पर मजबूर किया - भारत सस्ती चीनी वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भर है और व्यापार में कमी नुकसानदेह सिद्ध हो रही थी। इसलिए जब मोदी पिछले साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए कज़ान गए, तो रूस ने एक समझौता कराया, जिसमें मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इस महीने के अंत में, प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन जाएंगे, वहां शी जिनपिंग दुबारा भेंट होगी।

अब इतिहास का यह संक्षिप्त पाठ तभी उपयोगी हो पाएगा यदि जब आप निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य का अनुसरण करें। वह यह कि, भारत जहां एक ओर चीन के साथ तो अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहता है लेकिन ठीक उसी समय पाकिस्तान से बात तक करने से इनकार करता है। यहां यह दोहराना मौजूं है कि चीन-पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंध हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी साफ दिखाई दिए, जब भारतीय विमानों पर हमला करने में चीनी मिसाइलें पाकिस्तान की मददगार बनीं - यह किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीडीएस अनिल चौहान ने हाल ही में स्वीकार किया है।

तो अगर चीन-पाकिस्तान के बीच संरक्षक-ग्राहक संबंध का विस्तार काराकोरम से लेकर कराची तक है, तब रावलपिंडी सेना मुख्यालय से देश के राजकाज पर हावी फौजी जनरलों से बातचीत करने में मोदी के इनकार का क्या लाभ? इतना ही नहीं, ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में मुलाकात करने को एक बार फिर से आमंत्रित किया है- जो भारत के ज़ख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है।

पिछले हफ़्ते दूसरा सवाल यह है। क्या इस सारे वैश्विक पुनर्संतुलन का मतलब यह होना चाहिए कि भारत को व्लादिमीर पुतिन के पक्ष की ओर फिर से लौट जाना चाहिए, शीत युद्ध के दौर की तरह, जब हिंदी-रूसी भाई-भाई थे? लेकिन यहां पेंच यह है कि अगर मोदी ऐसा करेंगे, तो उन्हें वहां पहले से उपस्थित शी जिनपिंग मिल जाएंगे दृ क्योंकि शी और व्लादिमीर निकट सहयोगी हैं, जो एक-दूसरे को बेहतर समझते हैं। सनद रहे, बतौर कम्युनिस्ट दोनों की विचारधारा समान है। इसीलिए आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। नेहरू से लेकर वाजपेयी तक सभी प्रधानमंत्रियों की तरह मोदी को भी भान है कि अगर भारत चाहता है कि उसे गंभीरता से लिया जाए, तो उसे एक मज़बूत व स्वतंत्र ध्रुव बनना होगा। लेकिन ऐसा किया कैसे जाए जब बड़ी ताकतें खुद स र ` अ ा म कलाबाजियां खा रही हैं और कमज़ोर देशों का ताना-बाना हवा के थपेड़ों से बुरी तरह हिल रहा हो? चाणक्य और कन्फ्यूशियस के देशों का मिलन बनाना ज़रूरी है ताकि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार उनकी कहावतों में खुद को ढाल सकें यानि 'पत्थर छूकर पानी पार करो (कन्फ्यूशियस)' और 'साम, दाम, दंड, भेद(चाणक्य)' या माओ के कथनानुसारः 'बिल्ली काली है या सफ़ेद, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, जब तक वह चूहों को पकड़ने लायक है)। आर्थिक सुधारों ने कभी हिंदू विकास दर को अन्य गति दी थी और हमें अपने जीवनकाल में अभूतपूर्व दर से विकास करने में मदद की थी - उन्होंने भारत को उसकी विशिष्ट आत्मा प्रदान की। एक बार फिर, धर्म, जाति, वर्ग, पंथ, रंगों के आधार पर हमें बांटने और शासन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी को उस मध्य मार्ग पर वापस लौटना होगा जहां सभी नावें एक साथ उठती हैं। यही उनकी और भारत की ताकत है - एक ऐसी ताकत जो सब कुछ है।

ज्योति मल्होत्रा

अतिथि शिक्षक सूची अनुमोदन के नाम पर अटकी, कहीं नए तो कहीं पुराने को रखने का दबाव

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

शासकीय स्कूलों में पढ़ रहे गरीब बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी बानगी झाबुआ जिले में आसानी से देखी जा सकती है। एक तरफ़ मोहन सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है, परन्तु जिले में यह केवल दिखावे का ढकोसला और फोटोबाजी कराकर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार लेने तक ही सीमित है। वास्तव में धरातल पर स्थिति बिल्कुल अलग है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के खोखले नारे केवल शासकीय दीवारों पर ही दिखाई देते हैं।

जी हाँ, बात हो रही है जिले के शासकीय स्कूलों में चरमराई शिक्षा व्यवस्था की, जहाँ कई स्कूल शिक्षकविहीन हैं और कई स्कूल केवल एकल शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। शासन के स्पष्ट निर्देश थे कि 1 अगस्त से अतिथि शिक्षकों को पढ़ाने हेतु आमंत्रित किया जाना था, परन्तु यहाँ आज तक आमंत्रण तो दूर, संकुल स्तर पर कुछ जुगाड़ और कुछ पदनाम की बैसाखी के सहारे जिम्मेदार अधिकारी बने बैठे हैं। ये अधिकारी शासन-प्रशासन और हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाकर, खुद के बनाए नियम थोपकर अतिथियों की नियुक्ति में अड़ंगे डाल रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है।

1 अगस्त तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज दिनांक तक जिले से अतिथि शिक्षकों की सूची अनुमोदित नहीं हो पाई है। कुछ संकुल प्राचार्य अपने चहेते व नाते-रिश्तेदारों को इन पदों पर नियुक्त करने के लिए अपने हिसाब से नियम बना रहे हैं, जबकि कुछ नियमों के तहत केवल पुराने अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

पेटलावद ब्लॉक की स्थिति तो पूरे जिले से अलग है। यहाँ कुछ प्रभारी प्राचार्यों के अतिथि शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़े के मामले पूर्व वर्षों में सामने आए थे। परंतु जांच के नाम पर केवल कागज काले किए गए, कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि आज भी सही जांच हो तो प्रशासन को पता चलेगा कि, किस तरह नाते-रिश्तेदारों को नियुक्त कर काबिलों को बाहर का रास्ता दिखाया गया।

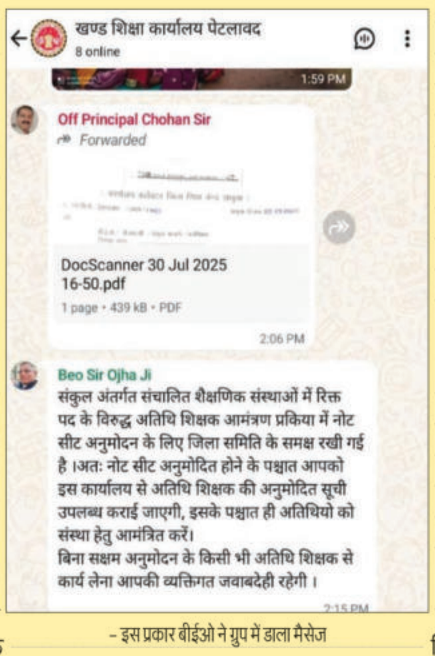

खण्ड शिक्षा कार्यालय पेटलावद
8 online

1:59 PM

Off Principal Chohan Sir
Forwarded

DocScanner 30 Jul 2025 16-50.pdf
1 page • 439 kB • PDF

2:06 PM

Beo Sir Ojha Ji
संकुल अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रकिया में नोट सीट अनुमोदन के लिए जिला समिति के समक्ष रखी गई है ।अतः नोट सीट अनुमोदित होने के पश्चात आपको इस कार्यालय से अतिथि शिक्षक की अनुमोदित सूची उपलब्ध कराई जाएगी, इसके पश्चात ही अतिथियो को संस्था हेतु आमंत्रित करें।
बिना सक्षम अनुमोदन के किसी भी अतिथि शिक्षक से कार्य लेना आपकी व्यक्तिगत जवाबदेही रहेगी ।

2:15 PM

– इस प्रकार बीईओ ने ग्रुप में डाला मैसेज

दो माह बीत गए नए शिक्षा सत्र को, 20 अगस्त के बाद त्रैमासिक परीक्षा

नया शिक्षा सत्र शुरू हुए लगभग दो माह से अधिक हो चुके हैं और 20 अगस्त के बाद से त्रैमासिक परीक्षा होनी है। लेकिन आज तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति न होने से कई महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, जिससे बच्चों का कोर्स समय पर पूरा होना मुश्किल है। कई स्कूल नियमित शिक्षकों के अभाव में अतिथियों के भरोसे ही हैं। पेटलावद ब्लॉक के कई स्कूलों में प्राचार्यों ने अपने विवेक से पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित कर लिया था, और ये अतिथि बिना वेतन के ही छात्रहित में निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। लेकिन बीईओ साहब ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए सभी स्कूल प्रमुखों को संदेश भेजा कि, संकुल अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया की नोटशीट अनुमोदन हेतु जिला समिति के समक्ष रखी गई है। नोटशीट अनुमोदित होने के पश्चात इस कार्यालय से आपको अतिथि शिक्षक की अनुमोदित सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके पश्चात ही अतिथियों को संस्था में आमंत्रित करें। बिना सक्षम अनुमोदन के किसी भी अतिथि शिक्षक से कार्य लेना आपकी व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। पहले जिले के जनजाति विभाग से आदेश जारी हुआ था कि, 30 जुलाई तक सूची अनुमोदित कर 1 अगस्त से अतिथियों को स्कूलों में आमंत्रित किया जाए, जो आज दिनांक तक नहीं हो पाया है।

6 विकासखंडों की जांच के लिए चार लोगों का दल

स्थानीय संकुल प्राचार्यों द्वारा अनुमोदन के बाद सूची बीईओ कार्यालय में भेजी गई, जहाँ से बनाई गई समिति ने जांच कर सूची सहायक आयुक्त झाबुआ को भेज दी। मामला अलग-अलग नियमों के बीच उलझ गया, तो सहायक आयुक्त झाबुआ ने चार सदस्यीय समिति गठित की, जो जिले के 6 विकासखंडों से प्राप्त आवेदनों की जांच कर सूची अनुमोदित कर भेजेगी। इस समिति को 6 अगस्त तक सूची अनुमोदित करनी थी, लेकिन आज दिनांक तक जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और सूची अनुमोदित होकर नहीं आई।

आखिर आज तक सूची का अनुमोदन नहीं होने का जिम्मेदार कौन है...? आदेश की समय सीमा में प्रस्तुत न करने की लेटलतीफी के पीछे कौन लोग हैं...? क्या इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही होगी, जो पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं...? इसका खामियाजा तो गरीब बच्चे और उनका भविष्य भुगत रहा है। लाखों रुपए मासिक वेतन पाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को न तो बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था की चिंता है, न ही बच्चों के भविष्य की। वहीं जिला कलेक्टर भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं, जिससे जनजातीय कार्य विभाग की लापरवाही के चलते उनकी साख पर भी बट्टा लग रहा है।

क़स्बे में धूमधाम से निकली तिरंगा यात्रा, देश भक्ति के नारों से गूंज उठा संपूर्ण यात्रा मार्ग

माही की गूंज, आम्बुआ।

स्वतंत्रता दिवस के दो दिन पूर्व क़स्बे में एक विशाल तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिलों पर निकाली गई सैकड़ों की संख्या में राष्ट्र भक्तों का जज्बा देखते ही बनता था हाथ में तिरंगा तो सर पर तिरंगे के रंगों की पगड़ी तथा टोपी पहने देश प्रेम के नारों से आसमान गुंजायमान कर रहे थे। रैली का समापन मां पार्वती मेमोरियल स्कूल में हुआ जहां पर उपस्थित समुदाय को संबोधित किया गया।

इन दिनों संपूर्ण भारत वर्ष के साथ ही मध्यप्रदेश एवं आलीराजपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है इसी कड़ी में बुधवार को आम्बुआ में भी क्षेत्रीय सांसद श्रीमती अनीता चौहान, प्रदेश सरकार के केबीनेट मंत्री नागरसिंह चौहान, जिला भाजपा अध्यक्ष संतोष परवाल, पूर्व विधायक माधौसिंह डावर, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश अग्रवाल आदि के मार्ग दर्शन में यह विशाल तिरंगा यात्रा सैकड़ों मोटरसाइकिलों पर निकाली गई। डी.जे पर बजते देश भक्ति के तरानों पर झूमते राष्ट्रभक्तों का जोश देखते ही बनता था क़स्बे से घूमते हुए यह रैली मां पार्वती मेमोरियल स्कूल पर जाकर समाप्त हुई जहां पर उपस्थित जनसमूह को केबीनेट मंत्री नागरसिंह चौहान ने संबोधित किया कार्य क्रम समापन पर मंडल अध्यक्ष भरत माहेश्वरी ने आभार व्यक्त किया।

तिरंगा यात्रा की इसी कड़ी में बुधवार दोपहर को पी.एम श्री उ मा विघालय आम्बुआ द्वारा सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राओं को साथ लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्ग दर्शन में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें देश भक्ति के नारों से आसमान गुंजायमान हो रहा था रैली क़स्बे से होकर पुनः शाला प्रांगण में पहुंची जहां पर राष्ट्रीय गीत के साथ समापन किया गया।

नेमिषारण्य में श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ, भाभरा के चौहान परिवार कथा के यजमान

माही की गूंज, नेमिषारण्य (यूपी)। राहुल चौहान

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नेमिषारण्य एक ऐसा धार्मिक स्थान है, जहाँ सूत जी ने सत्यनारायण कथा की थी व वेदव्यास जी के मुखारविंद से भागवत कथा हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ 18 पुराणों का वाचन हुआ है।

ग्रंथों में वर्णन है कि ऋषियों ने जब ब्रह्मा जी से कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए कोई स्थान बताने का अनुरोध किया, तब ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से एक चक्र उत्पन्न किया और उस चक्र को ऋषियों की ओर भेजते हुए कहा कि यह चक्र जहाँ स्थापित होगा, वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त होगा। यह चक्र गोमती नदी के किनारे एक वन में गिरा, जिसे नेमिषारण्य कहा गया। यहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होता।

यहाँ ललिता देवी नाभि शक्ति पीठ है। इसी स्थान पर ब्रह्मा जी का सुदर्शन चक्र शक्तिपीठ कुंड में गिरा और इस कुंड का नाम ब्रह्मचक्र कुंड पड़ा। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कुंड में अपने माता-पिता के नाम से 2 परिक्रमा करता है, उसे जगत जननी माँ और जगत के पिता ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पितरों की भी मुक्ति होती है कृ ऐसी मान्यता है।

इस धार्मिक स्थान पर देश-विदेश के लोग यह मंशा रखते हैं कि वे नेमिषारण्य की पावन धरा पर जाकर कथा का आयोजन करें। यहाँ कथा आयोजनों के लिए कई धर्मशालाएँ व पंडाल उपलब्ध हैं। जो व्यक्ति जिस स्तर पर कथा करवाना चाहता है, करवा सकता है।

इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर (भाभरा) के स्वर्गीय सम्पतलाल जी चौहान के ज्येष्ठ पुत्र नंदललाल चौहान एवं परिवार द्वारा अपनी माताजी प्यारी बाई व स्वर्गीय पिता के सानिध्य में 13 अगस्त से 19 अगस्त तक श्रीमद भागवत कथा का आयोजन श्री बलराम धर्मशाला, नेमिषारण्य में किया जा रहा है।

पं. श्री ललित किशोर जी दाधीच (अबगांव खुर्द), जयशक्ति होम्मस, हरदा आश्रम ओंकारेश्वर के मुखारविंद से कथा के प्रथम दिन बताया गया कि नेमिषारण्य की इस धार्मिक भूमि के लिए भगवान भी तरसते हैं। ऐसी पावन धरा पर आकर कथा का स्मरण करना भगवान की कृपा से ही संभव होता है।

कथा में गुरुदेव ने विस्तार से बताया कि नेमिषारण्य तपोभूमि क्यों है, किस प्रकार ब्रह्मा जी का चक्र यहाँ विराजित हुआ और यह स्थान संतों के लिए तपोभूमि कैसे बना। कथा में पं. श्री ने समझाया कि अन्न का एक-एक कण और जीवन का एक-एक पल बहुत महत्व रखता है, जिसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। साथ ही उन्होंने नेमिषारण्य में श्रीमद भागवत कथा के स्मरण व आयोजन का महत्व बताया और कहा कि इस कथा का स्मरण मात्र करने से भवसागर पार हो जाता है।

बुधवार को कथा के प्रथम दिन कलश यात्रा श्री बलराम धर्मशाला से ब्रह्मचक्र कुंड तक निकाली गई। वहाँ परिक्रमा कर पुनः कथा स्थल, धर्मशाला में कलश यात्रा पहुँची और तत्पश्चात कथा प्रारंभ हुई।

कथा के स्मरण हेतु गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगभग 600 से अधिक श्रद्धालु पहुँचे। सभी श्रद्धालुओं के ठहरने व दोनों समय के भोजन-प्रसाद की व्यवस्था कथा के यजमान नंदललाल चौहान द्वारा की गई है। कथा दोपहर 12:30 बजे से 4 बजे के बीच सम्पन्न हुई।

स्वतंत्रता की महत्वपूर्णता सदा स्मरण रहे, जब देश पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तब लाखों लोग विभाजन का दंश झेल रहे थे

माही की गूंज, झाबुआ।

स्वतंत्रता की 78 वर्षगांठ आज भारत मना रहा है, स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसका अनुमान लगाना अत्यंत कठीन है। आज हम खुली हवा में अपने पंख फैलाए खुशियों के साथ रहते है क्योंकि इस स्वतंत्रता के लिए, लाखों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है, जिसे भूलाया नहीं जा सकता... मगर लोग भूल रहें हैं।

आज की युवा पीढ़ी को 15 अगस्त सन् 1947 के दूसरे पहलु का अनुमान ही नहीं है, जब देश स्वतंत्रता के उजाले में तीरंगा लहरा रहा था तब उसके पीछे विभाजन के घाव से रक्त, पीप, स्वेदकर्ण, दर्द के साथ बह रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरु की हठधर्मी से लाखों लोग बेघर हो गये थे, प्रतिदिन हजारों मौत के घाट उतर रहे थे, माताएं अपनी बेटियों का गला घोटकर उन्हें मौत दे रही थी और उसके बाद स्वयं की जीवनलीला समाप्त कर रही थी। फिर भी अधर्मी दुराचारी अपने दुराचार से बाज नहीं आ रहा थे उसने तो अपनी नफरत का प्रदर्शन करते हुए मृत देह से भी दुष्कर्म किया। लाखों युवतियों का अपहरण कर लिया गया, हजारों बच्चियों के साथ गलत काम किया, महिलाओं के साथ सामुहिक दुष्कर्म। ऐसी अनेकोनेक अंतहीन यातानाएं है जिसके बारे में जानकर समझकर विचार करना जरुरी है क्योंकि वह भी स्वतंत्रता का एक सच है...

वर्तमान में युवाओं को इन यातनाओं का कुछ प्रतिशत भी नहीं पता है, उन्हें जानकारी नहीं कि, विसत्थापन के दर्द में कितनी कसक कितने गहरे घाव मां भारती के शरीर के किस-किस अंगो पर लगे। मेरा अनुमान है कि, वर्तमान पीढ़ी को ऐसा कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि हमने देखा है, बच्चें और युवा पीढ़ी इस दिवस को छुट्टी मानकर पिकनीक मनाते हैं या आराम करते हैं या फिर शराब और मांसाहार के साथ पार्टिया करते हैं।

बीती सरकारों ने स्वतंत्रता की महत्ता को एक ऐसा उत्सव बना दिया है जिसमें भारतीय इस दिन को एक दिन का अवकाश मानकर आराम करते हैं, प्रशासन जिला, तहसील स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करवाकर इतिश्री कर लेता है। हर सरकारी निजी कार्यालय पर भारतीय ध्वज फहराया जाता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिष्ठान या अल्पाहार देकर छुट्टी कर दी जाती है। इतना कुछ किया जाता है बस। बरसो बरस की हमारी पराधिनता से स्वतंत्रता के सैकड़ो वर्षों के इस लंबे पीड़ादायी, अत्याचारी, दुखःद, यात्रा को एक दिवस के कुछ घंटो का उत्सव मनाकर अवकाश की तरह छोड़ दिया जाता है। किसी को बताया नहीं जाता कि किस तरह पीड़ा के सहते हुए हमने पराधिनता की सीमा को पार कर स्वतंत्रता के आंगन में पैर रखा।

सरकारों ने क्यूं नहीं इसे महत्वपूर्ण समझा कि भविष्य में देश के प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता के संग्राम के इतिहास की बारिकियां उसकी गहराइयों को जानने उसे समझने की आवश्यकता होगी। इसलिए स्वतंत्रता का महोत्सव मनाया जाए... प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाओ में इसे सात दिन के पर्व की तरह मनाया जाए, जिसमें नृत्य, कला, लेखन, नाटिकाएं, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे देश पर सैकड़ो वर्षों की पराधिनता का उल्लेख हो और किस तरह संग्राम करते हुए हमने दुश्मनों को खदेड़ा, और हमने ऐसी क्या गलतियां की, क्यों विफल हुए जो हमें हजारो वर्षों तक पराधिन रहना पड़ा। फिर किन कारणों की वजह से हमने विरोध किया और हम लड़े, यातनाएं सहते हुए रक्तरंजीत हुए, भूखे प्यासे, तिल-तिल मरते हुए भी हमने स्वतंत्रता के पथ को प्रबल बनाया, लाखों युवतियों और महिलाओ ने अपनी मर्यादा भंग न हो इसलिए स्वयं को मृत्यू की गोद में डालकर काल का ग्रास बन गई, और लाखो करोड़ो स्त्रियां बच्चियां उन नीच अधर्मी पापी असुरों की दुष्ट वासना का शिकार हुई। हमने शक्ति को किस तरह उपयोग कर स्वतंत्रता का सुरज देखा। इसे बताने के लिए हमें आज स्वतंत्रता महोत्सव की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक दिन के उत्वस की बात नहीं।

रिंकेश बैरागी

हमें हमारे देश को अगर पापाचिरयों दुराचारियों आत्याचारियों से बचना है तो हमें स्वतंत्रता महोत्सव की आवश्यकता है... क्योंकि वर्तमान में भी हमारे देश के दुश्मन हमें अगल-अगल तरह से परतंत्रता की तरफ धकेलने की कोशिश में लगे हुए है। वो धर्मांतरण करवाकर हमारी संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं वो परिवार को तोड़ कर महिलाओं को अपनो से अपनो का विरोधी बना रहे हैं।

सामाजिक संगठनों को अपने कार्यों के माध्यम से वर्तमान सरकार से यहीं अनुग्रह करना चाहिए कि, हमें हमारे देश में स्वतंत्रता महोत्वस मनाना चाहिए जो सात दिवस तक पर्व की तरह शैक्षणिक संस्थाओं में चले, जिससे हमारी भावी पीढ़ी परतंत्रता से स्वतंत्रता के पथ को समझे। उन यातानाओं को जाने, मां भारती के शरीर के उन घाव को युवा देखे और उस दर्द को भारतीय समझे।

सावधान! अगर भायल साहब का इगो हट हुआ तो भी आपका वैध क्लिनिक हो हो सकता है सील

क्लिनिक के बाहर जूते उतारने का कहा तो झल्ला उठा भायल, कर दिया क्लिनिक सील

जब इस घटना को डॉ.सोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेर किया तो बहुत सी प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी तो खुद चश्मदीद गवाह ने कर दी।

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मिल मंसूरी

कहते है जब आदमी को पद और प्रतिष्ठा मिलती है तो वह अपने संस्कार कचरे के डब्बे में डाल देता है और उसकी छवि में पद का पावर और प्रतिष्ठा घमंड बनकर झलकने लगती है। इसी के चलते वह अपने किए गए हर काम को अपनी ढपली, अपना राग की तर्ज पर सत्य ही समझता है। वह यह मान लेता है कि, वह जो कर रहा है वही सत्य है और बाकी सबकुछ असत्य। इसी गलत फहमी में वह ऐसी गलतियां भी करने लगता है, जो उसकी पद, प्रतिष्ठा और पावर को धुमिल कर देती है।

अभी पिछले कुछ दिनों से जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग का अमला झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ ऐसा जागा हुआ है कि, मानों अब वह जिले से तमाम झोलाछाप, बंगाली, बांग्लादेशी डॉक्टरों का सफाया ही कर देगा। यह और विषय है कि, अगर जिले में इतने झोलाछाप घूम रहे है तो अब तक स्वास्थ्य विभाग और उनके आका कौन सी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे...? या फिर झोलाछापों, बंगालियों , बांग्लादेशीओ से इतने लंबे समय तक स्वास्थ्य विभाग के संबंध शायद भेंट पूजा वाले रहे हो। अब जबकि कार्रवाई के निर्देश प्रदेश स्तर से बंबू के रूप में घुसे है तो स्वास्थ्य विभाग और उसमें बैठे आका दर्द से झल्ला उठे है। इसी झल्लाहट में विभागीय अमला और उसमें बैठे नोडल अधिकारी इस काम को लेकर इतने अतिउत्साही लाल बने हुए है कि, अब वे सही और गलत का फर्क करना ही भूलते जा रहे हैं। झोलाछाप और बंगाली/बांग्लादेशी डॉक्टरों के साथ ही वे उन डॉक्टरों पर भी उसी तेज व रूबाब से कार्रवाई कर रहे है जो अपने कर्तव्य को लेकर पिछले कई वर्षों से निष्ठा पूर्वक सेवा कार्य कर रहे है। उस पर सितम यह कि, कार्रवाई के दौरान इन अधिकारियों की भाषा शैली और व्यवहार मानों किसी गुंडे मवाली की भाषा प्रतीत हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के इन अधिकारियों पर पद और पावर का ऐसा जुनून है कि, वे प्रतिष्ठित डॉक्टरों से भी तू तड़ाक लहजे में बात कर रहे है। तू कब से काम कर रहा है...? तेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं...? हम पहले भी आए थे, तो तू भाग गया था...? तेरे पास कौन सी डिग्री है...? एक चिकित्सक और निरीक्षण टीम के नोडल अधिकारी की भाषा में इतनी तल्खी और खड़ी भाषा का इस्तेमाल यह बताता है कि, उनकी परवरिश कैसी हुई होगी! घटनाक्रम यह भी बताता है कि, भले इंसान पढ़ाई करके डिग्री और उच्च पद हासिल कर ले, लेकिन अगर उसके संस्कार ठीक नहीं तो वह पढ़ाई और डिग्री किसी काम की नहीं।

मंगलवार को एक ऐसा मामला सामने आया। जिसने स्वास्थ्य विभाग और उसमें बैठे अधिकारियों के द्वारा की जा रही कार्रवाईयों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए है। हुआ कुछ यूं कि, निरीक्षण टीम में शामिल चिकित्सक और नोडल अधिकारी भायल मंगलवार को लगभग 12 बजे सीधेश्वर कॉलोनी स्थित एक क्लिनिक पर पहुंच गए। क्लिनिक का नाम था सावित्रि क्लिनिक एंड हेल्थ केयर। बोर्ड पर क्लिनिक के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर का नाम और उसकी डिग्री भी लिखी हुई थी। क्लिनिक के बाहर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि, कृपया जूते-चप्पल बाहर निकाल कर ही आएं। मगर साहब तो साहब ठहरे, अपने पद और पावर के गुरूर में दनदनाते हुए जुतों सहित क्लिनिक में बिना किसी प्रवेश अनुमति के घुस गए। क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर नितिन सोनी अपने पैसेंट को देख रहे थे। निरीक्षण टीम के अधिकारी भायल ने अपना परिचय दिए बगैर ही गुंडों की तरह सवाल दागना शुरू कर दिए। तू कब से काम कर रहा है....? तेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है....? भौचक्के रह गए डॉक्टर नितिन सोनी ने यह सब देखते हुए कहा आप कौन है...? पहले अपने जूते बाहर निकाल कर आईये...? बस फिर क्या था भायल साहब का ईगो हट कर गया और उनकी भाषा शैली इतनी गिरती चली गई कि, अब वे सीधे तौर पर तू-तड़ाक और गुंडे मवाली जैसी भाषा का उपयोग करने लगे। जब डॉक्टर ने कहा कि, आखिर आप है कौन और किस तरह की भाषा का उपयोग मेरे क्लिनिक में कर रहे है। तब रौब झाड़ते हुए भायल साहब कहने लगे मैं डॉक्टर भायल नोडल अधिकारी हूं...। यह सुनकर डॉक्टर ने उन्हे कहा कि जी आप नोडल अधिकारी है मगर मैं आपको बायफेस नहीं जानता, हां नाम जरूर सुना है। इसके बाद साहब अपने रूबाब में क्लिनिक के कागजात और डॉक्टर सोनी की डिग्रियां जांचने लगे। जांच में डॉक्टर की डिग्री सही, भोपाल से जारी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन जो 2026 तक मान्य था। क्लिनिक से किसी तरह की कोई ऐलोपैथिक दवाई नहीं मिली। इस सारे निरीक्षण का पंचनामा भी बनाया गया। जिस पर डॉक्टर नीतिन सोनी ने हस्ताक्षर भी किए। डॉक्टर नीतिन सोनी के अनुसार वे पिछले 12 वर्षों से होम्योपैथी पद्धति से ही लोगों का इलाज कर सेवाएं प्रदान कर रहे है। मगर अब कुछ भी करके यह क्लिनिक सील तो होना ही था क्योंकि साहब का इगो जो हट हो चुका था। तब बात को वहां ले जाकर अटका दिया गया जो शायद इतना जरूरी नहीं था। नोडल अधिकारी डॉक्टर भायल ने सिर्फ एक छोटे से सर्टीफिकेट की वजह से क्लिनिक सील कर दिया जो जिला मुख्यालय से ही सीएमएचओ कार्यालय से जारी होता है। हालांकि डॉक्टर सोनी के पास वह भी मौजूद था लेकिन वह 2019 तक ही मान्य बताया जा रहा है। स्थिति यह हो सकती थी कि, डॉक्टर नितिन सोनी को नोडल अधिकारी भायल समय दे देते कि इस सर्टीफिकेट को जल्द रिनिवल करा लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि साहब का इगो तो हट हो ही चुका था। नतीजा यह निकला कि, भायल साहब बिना किसी ठोस वजह के क्लिनिक सील करके रवाना हो गए और साथ में यह धमकी भी दे गए कि, आ अब तेरे को देखता हु...।

सूत्रों के अनुसार इतना सब होने के बाद भायल साहब ने डॉक्टर नितिन सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें संभवतः यह कहा गया कि, डॉक्टर नितिन सोनी ने निरीक्षण के दौरान दादागिरी की और धमकी भी दी।

अब अगर बात जिले की स्थिति की करें तो यह बिल्कुल साफ है कि जिले में बंगालियों/बांग्लादेशीओ और झोलाछापों की बाढ़ बरसों से आई हुई है। मगर विभाग और भायल साहब पर कार्रवाई करने का भूत अब सवार हुआ है। पिछले दिनों पड़ोसी जिले आलीराजपुर के एक कस्बे में झोलाछाप डाक्टर के इलाज से हुई एक मौत ने तूल पकड़ लिया था। जिसके बाद जिले में भी इन पर कार्रवाई की मांग उठने लगी। नतीजा यह सामने आया कि प्रदेश स्तर से निर्देशो का बंबू जिला अधिकारियों को हुआ और इसी मजबूरी के चलते झाबुआ जिले में भी झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया। मगर इसकी असल हकीकत कोई नही जानता कि, आखिर जिले में यह कार्रवाईयां किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हो रही है। जब-जब अखबार, झोलाछाप और बंगालियों/बांग्लादेशी के मुद्दे उठाते है तब -तब यही विभाग और इसमें बैठे आला अधिकारी अपनी पिपड़ी बजाते हुए निकलते है और एकाध झोलाछाप पर कार्रवाई कर इतिश्री कर लेते है। विडम्बना यह कि जब भी विभाग या उसके आला सिखंडी अधिकारी कार्रवाई के लिए निकलते झोलाछाप और बंगालियों को पहले ही इसकी खबर पहुंचा दी जाती और वे अपने ठिकाने से रफुचक्कर हो जाते। यह कोई सामन्य बात नहीं है कि , विभागीय टीम के आने की खबर पहले ही पहुंच जाए। इसमें भी एक बहुत बड़ा झोल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इस स्थिति से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि, झोलाछाप और बंगाली कहीं न कहीं किसी न किसी की तो भेंट-पूजा करते ही है। जो उन्हे कार्रवाई के पहले ही रफुचक्कर हो जाने की खबर दे देता। इस बात में भी कोई दो मत नहीं कि, जो इन बंगालियों और झोलाछापों से भेंट -पूजा लेता होगा वह इसे अकेले हजम करता होगा। कहीं न कहीं यह हिस्सा उपर तक भी तो जाता होगा! हम यहां किसी पर कोई आरोप नही लगा रहे बल्कि स्थिति ही ऐसी बनी हुई है जो स्पष्ट रूप से इशारे करती है कि, बांस पूरा पोला तो है ही। हो सकता है कि, भायल साहब की क्लिनिक सील करने के पीछे भी कोई इसी तरह की मंशा हो...? क्योंकि अब तक तो यही होता आया है। जिले में जिन जगहों पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई की नौटंकी करता है वह महज कुछ ही दिनों में फिर से सुचारू रूप से संचालित होते दिखाई देते है। इसे प्रमाण की कोई आवश्यक्ता ही नहीं है। सील किए गए क्लिनिक किस आधार पर फिर से शुरू हो जाते है इसका कोई स्पष्टीकरण स्वास्थ्य विभाग या अधिकारियों के पास नहीं है।

रही बात सावित्रि क्लिनिक और डॉ. नितिन सोनी की तो पिछले 12 वर्षों से जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी पद्धति से कई गंभीर मरीजों को ठीक कर चुका है, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरूस्कार ले चुका है। अब भी ऐस कई मरीज उनके क्लिनिक पर पहुंचते है जो गंभीर बिमारियों से ग्रसित है। शहर के प्रतिष्ठित लोग भी इनसे इलाज लेते है। वे इस बात के गवाह है कि, यहां कैसा और किस पद्धति का इलाज होता है। मगर अफसोस कि, महज जूते बाहर निकालने की बात पर डॉक्टर भायल का इगो हट हो जाता है और वे इस क्लिनिक को सील कर यह धमकी देते है कि, आ अब तूझे मैं देखता हूं... ! कहां तक उचित है....?

डॉ. नितिन सोनी के क्लिनिक और उनकी डिग्री तमाम कागजात सही पाए गए। केवल एक सर्टीफिकेट जो सीएमएचओ कार्यालय से जारी होता है, वह एव सपायर हो चुका था। जो इतना भी महत्वपूर्ण नही था कि क्लिनिक सील कर दिया जाए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422